दैनिक
साधना एक्सप्रेस

वर्ष-4 | अंक -38 | sadhnaexpress@gmail.com | भोपाल, शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 | पृष्ठ-8 | मूल्य - 2 रुपये | www.sadhnaexpress.com

न्यूज ब्रीफ

यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, सीजेआई ने कहा- 'ऐसा मत कीजिए, हम पीछे जा रहे हैं...'

नई दिल्ली, एजेंसी | 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में UGC के नए नियमों के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने नियमों पर रोक लगा दी. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नया नियम भ्रम पैदा करता है.

सुप्रीम कोर्ट में UGC के नए नियमों के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए रोक लगा दी. 29 जनवरी 2026 को हुई सुनवाई में CJI सूर्यकांत की बेंच ने फैसला सुनाया और सरकार को नोटिस जारी कर के जवाब मांगा है.

UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अभी 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 2026 तक केंद्र सरकार और UGC को नोटिस जारी कर के जवाब मांगा है. यानी अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी.

CJI सूर्यकांत ने नियमों पर रोक लगाते हुए पूछा कि क्या हम जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? हमने देखा है कि हॉस्टल में छात्र एक साथ रहते हैं. नए नियमों से अलग हॉस्टल बन जाएंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए. इस बीच जस्टिस बागची ने भी कहा कि समाज और देश में एकता के लिए काम करना चाहिए.

CJI सूर्यकांत ने कहा, 'हम सरकार से जवाब लेंगे. ऐसी परिस्थिति से कुछ लोग लाभ ले सकते हैं. एक विशेषज्ञ कमिटी भी बनाई जा सकती है.'

याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा, 'संविधान ने सबको संरक्षण दिया है. सभी नागरिकों की रक्षा होनी चाहिए. लेकिन नया नियम भ्रमित करता है और समाज में भेदभाव पैदा करता है. इसमें सिर्फ OBC, SC और ST की बात की गई है.'

चुनाव से पहले ममता सरकार ने EC की सूची पर उठाए सवाल, नौ IAS अफसरों के नाम बदलने का भेजा प्रस्ताव

कोलकाता, एजेंसी | पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग की ओर से जारी केंद्रीय पर्यवेक्षकों की सूची पर आपत्ति जताते हुए इसमें बदलाव की मांग की है। राज्य सरकार ने आयोग को पत्र लिखकर 15 में से 9 आईएएस अधिकारियों के नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा है, जिनमें राज्य के गृह सचिव भी शामिल हैं।

वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, यह प्रस्ताव प्रशासनिक और आधिकारिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भेजा गया है। सरकार का कहना है कि जिन अधिकारियों के नाम सुझाए गए हैं, वे राज्य में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर कार्यरत हैं, ऐसे में चुनावी ड्यूटी से उनकी अनुपस्थिति प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है।

राज्य सरकार के पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है और अंतिम फैसला आयोग द्वारा लिया जाएगा। इससे पहले आयोग ने पश्चिम बंगाल से 25 वरिष्ठ अधिकारियों की सूची जारी की थी, जिन्हें पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया जाना है।

सूची जारी करने के साथ ही आयोग ने सभी चयनित अधिकारियों के लिए अनिवार्य ब्रीफिंग सत्रों के निर्देश भी दिए हैं, ताकि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और सुचारु ढंग से संपन्न कराई जा सके। इस घटनाक्रम को चुनावी तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की भूमिका एक बार फिर चर्चा में आ गई है।

अब यमुनोत्री धाम में भी गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक, बदरी-केदार व गंगोत्री में भी एंट्री नहीं

गंगोत्री धाम के बाद अब यमुनोत्री धाम में भी गैर सनातनियों के प्रवेश को वर्जित करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले हरकी पैड़ी और बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर में भी गैर सनातनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है।

• नई दिल्ली, एजेंसी

नई दिल्ली | गंगोत्री धाम के बाद अब यमुनोत्री धाम में भी गैर सनातनियों के प्रवेश को वर्जित करने का निर्णय लिया गया है। यमुनोत्री मंदिर समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि आगामी अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान धाम में नियम लागू कर दिया जाएगा। वहीं प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज सहित अन्य संतों के साथ हुए दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए दुर्व्यवहार की निंदा

यमुनोत्री मंदिर समिति के प्रवक्ता पुरुषोत्तम उनियाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि यूपी के प्रयागराज में जिस तरह स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को स्नान करने से रोका गया उससे सनातनियों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यह सनातन धर्म के खिलाफ है और सनातन धर्म के प्रहरियों की आवाज दबाने की साजिश रची जा रही है।

चारधाम यात्रा के दौरान धाम में नियम लागू होगा

उन्होंने कहा सनातन की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार हैं। यमुनोत्री धाम में भी गैर सनातनियों के प्रवेश को वर्जित करने का निर्णय लिया गया है। इस बार चारधाम यात्रा के दौरान धाम में नियम लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी भी गैर सनातनी को धाम के आसपास प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इस मौके पर बड़कोट व्यापार मंडल महामंत्री सोहन गैरोला भी रहे।

बीकेटीसी के अधीन आने वाले मंदिरों में भी रोक

बदरीनाथ, केदारनाथ धाम के अलावा बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अधीन आने वाले 45 से ज्यादा मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा। बीकेटीसी की ओर से आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाएगा।

हरकी पैड़ी पर जगह-जगह लगा दिए गए बोर्ड

तीर्थ की मर्यादा बनाए रखने के लिए श्रीगंगा सभा ने हर की पैड़ी समेत कई घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को निषेध कर दिया। इस बारे में विभिन्न जगहों पर बैनर व बोर्ड लगा दिए गए हैं। श्रीगंगा सभा ने ब्रिटिश हुकूमत में लागू म्यूनिसपल एक्ट के तहत यह कदम उठाया है। बोर्ड में स्पष्ट रूप से चेतावनी लिखी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

हरकी पैड़ी समेत मालवीय द्वीप व अन्य घाटों पर लगे इन बैनरों की शुक्रवार को लोगों को चर्चा रही। इसमें श्रीगंगा सभा ने स्पष्ट तौर पर लिख दिया कि घाटों पर किसी तरह से फिल्मी गीत पर वीडियो या रील्स बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यदि किसी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इस तरह के वीडियो प्रसारित होते दिखे तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। मामले को लेकर प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। वहीं व्यापारी से लेकर आमजन इसे सनातन की रक्षा में उठाया गया कदम बता रहे हैं।

भावांतर भुगतान योजना किसानों की तपोसाधना और समर्पण का सम्मान : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

• भोपाल संवाददाता

भोपाल | मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मौसम कोई भी हो, किसानों को हमेशा अपने खेत-खलिहान की ही चिंता रहती है। फसल अच्छी हो, तो पूरे साल की हरियाली... पर किसी वजह से कम पैदावार हो जाए, कीड़ा लग जाए, ओला-पाला से फसल खराब हो जाए, तो फिर पूरे साल का सूखा। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसान हमारे अन्नदाता हैं, इन्हें कोई भी परेशानी हो, कठिनाई हो, तो हमारी सरकार किसानों का संबल और इनकी ढाल बनकर हमेशा साथ खड़ी है। किसान हमारी संस्कृति का आधार हैं, हमारी धरोहर हैं और प्रदेश की अर्थव्यवस्था के वास्तविक कर्णधार हैं। किसानों की जिंदगी बेहतर बनाना, इनके खेत, खलिहानों और घरों में समृद्धि लाना ही हमारा एकमात्र ध्येय है। किसानों की समृद्धि में ही प्रदेश की समृद्धि है। सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना किसानों के जीवन

में समृद्धि लाने के लिए सरकार का प्रयास है। यह योजना किसानों के कठिन तप, साधना और समर्पण का सम्मान है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में 'अन्नदाता सम्मान समारोह' को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना की अंतिम किश्त के रूप में प्रदेश के 1 लाख 17 हजार किसानों के खातों में लगभग 200 करोड़ रूपए की भावांतर राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि योजना के प्रारंभ से अब तक 7 लाख 10 हजार से अधिक किसानों को हमारी सरकार लगभग 1500 करोड़ रूपए की भावांतर राशि सोयाबीन उत्पादक किसानों को दे चुकी है। आज जिन किसानों को भावांतर की राशि मिली है, उसमें मंदसौरजिले के किसान भी शामिल हैं। मंदसौर जिले के 27 हजार से अधिक किसानों को लगभग 43 करोड़ रूपए की भावांतर राशि मिली है।

सरकारी और निजी बैंकों से 2.5 गुना हुई इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की पहुंचः सिंधिया

• नई दिल्ली, एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज सदन में भारतीय डाक विभाग की राष्ट्रीय उपलब्धियों, डिजिटल परिवर्तन और सेवा विस्तार से जुड़े कई महत्वपूर्ण आँकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि इंडिया पोस्ट आज न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व की सबसे व्यापक और प्रभावी वितरण प्रणाली के रूप में कार्य कर रहा है, जो डाक और पार्सल के साथ-साथ नागरिकों तक सरकार और निजी क्षेत्र की लगभग हर सेवा पहुँचाने में सक्षम है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश के साढ़े छह लाख से अधिक गाँवों में फैले 1,65,000 डाक केंद्रों के माध्यम से इंडिया पोस्ट देश का सबसे बड़ा सेवा नेटवर्क संचालित कर रहा है, जिसमें से लगभग 90 प्रतिशत केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। केन्द्रीय मंत्री ने साथ ही बताया कि डाक विभाग आईटी 2.0 और एपीटी के साथ तेजी से

डिजिटल समावेशन कर रहा है और साथ ही इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है।

सिंधिया ने बताया कि डाक विभाग में वित्तीय समावेशन में ऐतिहासिक प्रगति की है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत देशभर में लगभग 3.75 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के अंतर्गत करीब 38 करोड़ खाते सक्रिय हैं, जिनमें लगभग 22 लाख करोड़ का डिपॉजिट है, जो पिछले दस वर्षों में 6 लाख करोड़ से बढ़कर साढ़े तीन गुना हो चुका है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB), जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, आज 13 करोड़ खाताधारकों तक पहुँच चुका है और इसके माध्यम से अब तक लगभग 1,37,000 करोड़ की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर राशि वितरित की जा चुकी है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत लगभग 1.25 करोड़ खाते हैं, जिनमें 2 लाख करोड़ से अधिक का डिपॉजिट है।

कांग्रेस में 'सब ठीक है'? शशि थरूर ने खरगे -राहुल से मुलाकात के बाद दिया बड़ा संदेश

• नई दिल्ली, एजेंसी

नई दिल्ली | कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने संसद कार्यालय में लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की। यह मुलाकात पिछले आधे घंटे से चल रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में दिए गए उनके बयानों के बाद शशि थरूर के कांग्रेस से संबंध अच्छे नहीं हैं। पिछले हफ्ते थरूर ने कहा था कि पार्टी से उन्हें कुछ 'मतभेद' हैं, जिन्हें वे नेतृत्व के समक्ष उठाएंगे, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने संसद में

संगठन के घोषित रुख का कभी उल्लंघन नहीं किया है।

खरगे और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शशि थरूर ने कहा कि मैं किसी पद के लिए उम्मीदवार नहीं हूं। मैं पार्टी के लिए प्रचार कर रहा हूं। मैं बहुत संतुष्ट हूं। उन्होंने कहा कि आज विभिन्न विषयों पर सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक चर्चा के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा सांसद राहुल गांधी का धन्यवाद। भारत की जनता की सेवा में आगे बढ़ने के लिए हम सभी एकमत हैं। उन्होंने कहा कि आंतरिक मतभेदों पर संगठन के भीतर ही चर्चा होनी चाहिए, न कि मीडिया के माध्यम से।

बीएचयू में बवाल, दो गुटों के छात्रों में पत्थरबाजी, भारी फोर्स, ड्रोन से हॉस्टल के छतों की निगरानी

• नई दिल्ली, एजेंसी

नई दिल्ली | वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) में गुरुवार (29 जनवरी) को बवाल हो गया. दो होस्टल के छात्र आमने-सामने हो गए. पत्थरबाजी भी हुई है. भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है. एक छात्र के घायल होने की खबर है. स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास जारी हैं. काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवानों ने मार्च किया.

काशी जोन के पुलिस उपायुक्त

(डीसीपी) गौरव बंसवाल ने बताया कि रुइया हॉस्टल और बिरला हॉस्टल के छात्रों के बीच जन्माष्टमी पर जो कहासुनी हुई थी उसकी को लेकर आज फिर से विवाद हुआ. उसी में दो छात्रों के गुट आपस में लड़ लिए. हमें सूचना मिली कि इनमें आपस में पत्थरबाजी हो रही है. तत्काल भारी फोर्स मौके पर आ गया. छात्र यहां से भाग गए. जो छात्र चोटिल हुआ है उसको ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है.

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, घायल छात्र ने कुछ ऐसे छात्रों के नाम बताए हैं जो यहां के पूर्व छात्र हैं और अनाधिकृत रूप से यहां रह रहे हैं. इन्हीं को चिह्नित करने लिए कार्रवाई की जा रही है. ड्रोन से सभी हॉस्टल के छतों की निगरानी की जा रही है.

पार्थ और जय ने पिता को दी मुखाग्नि, भतीजे की विदाई देख मौन हुए शरद पवार, गमगीन रहा बारामती का नजारा

• नई दिल्ली, एजेंसी

नई दिल्ली | महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, उपमुख्यमंत्री और NCP प्रमुख अजित पवार का गुरुवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अंतिम संस्कार किया गया। अपने पसंदीदा नेता की एक झलक पाने और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बारामती की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। उनकी अंतिम यात्रा में समर्थकों की रुलाई और 'अजित दादा परत या' (अजित दादा वापस आओ) के नारों ने माहौल को और भी गमगीन कर दिया। अंतिम संस्कार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित कई बड़े नेता

मौजूद थे। अंतिम संस्कार के दौरान अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और उनके दोनों बेटे, पार्थ और जय, उपस्थित थे। नम आंखों के साथ दोनों बेटों ने अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। बारामती के काटेवाड़ी गांव से लेकर विद्या प्रतिष्ठान तक, हर आंख नम थी। एक समर्थक ने रोते हुए कहा, 'अजित दादा ने इस क्षेत्र को नई पहचान दी, उनके जैसा विकास पुरुष दोबारा नहीं होगा।'

केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, रामदास अठावले, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे और आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने पवार के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित किए।

एआई पर पीएम मोदी का मास्टरप्लान, भारत को ग्लोबल हब बनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई क्षेत्र के सीईओ और विशेषज्ञों से भारत को वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक प्रमुख केंद्र बनाने का आह्वान किया, जिसमें एक पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित इकोसिस्टम के विकास पर जोर दिया गया। उन्होंने यूपीआई की सफलता का उदाहरण देते हुए डेटा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण के महत्व को रेखांकित किया।

• नई दिल्ली, एजेंसी

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में कार्यरत मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) और विशेषज्ञों से बातचीत की और इस बात पर जोर दिया कि एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है जो 'पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित' हो। उन्होंने एआई के नैतिक उपयोग पर भी कोई समझौता न करने की बात कही और प्रमुख क्षेत्रों में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग का आह्वान किया।

7, लोक कल्याण मार्ग (एलकेएम) स्थित अपने कार्यालय में हुई इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने सीईओ से भारत को वैश्विक एआई प्रयासों के लिए एक 'उपयुक्त केंद्र' बनाने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि देश ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से अपनी तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन किया है और इसे एआई के क्षेत्र में भी दोहराया जा सकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में कहा कि पीएम मोदी ने डेटा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने यह भी अपील की कि भारत में एआई इकोसिस्टम देश के चरित्र और मूल्यों को प्रतिबिंबित करे, साथ ही एआई कौशल विकास और प्रतिभा निर्माण की आवश्यकता पर भी बल दिया।

पीएमओ ने कहा कि आगामी एआई इम्पैक्ट समिट के बारे में बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सभी व्यक्तियों और कंपनियों को नए अवसरों का पता लगाने और विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए इस समिट का लाभ उठाना चाहिए। पीएमओ ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत के पास विशालता, विविधता और लोकतंत्र का अनूठा संयोजन है, जिसके कारण दुनिया भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे पर भरोसा करती है।

पीएमओ ने कहा कि सभी के लिए एआई' के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपनी प्रौद्योगिकी से प्रभाव पैदा करने के साथ-साथ दुनिया को प्रेरित करने की भी आवश्यकता है। इस उच्चस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक, जोहो कॉर्पोरेशन, एलटीआई माइंडट्री, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, अदानीकॉनेक्स, एनएक्सट्रा डेटा और नेटवेब टेक्नोलॉजीज सहित एआई क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों के सीईओ ने भाग लिया। इनके अलावा, IIIT हैदराबाद, IIT मद्रास और IIT बॉम्बे के विशेषज्ञ भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी बैठक में शामिल हुए।

कौन हैं भगवानदास रायकवार, जिन्होंने 'बुंदेली मार्शल आर्ट' को दी नई पहचान, अब राष्ट्रपति देंगे 'पद्मश्री' सम्मान

'बुंदेली मार्शल आर्ट': पद्मश्री पुरस्कार 2026 के लिए मध्य प्रदेश के सागर से भगवानदास रायकवार का नाम सूची में शामिल हैं। विलुप्त होती 'बुंदेली मार्शल आर्ट' को जीवित रखने वाले रायकवार को भारत सरकार ने 'अनसंग हीरोज' श्रेणी में पुरस्कार के लिए चुना है।

• सागर, प्रतिनिधि

सागर | भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार 2026 के लिए मध्य प्रदेश में सागर जिले के अखाड़ा गुरु भगवानदास रायकवार को चुना गया है। एकदम से चर्चाओं में आए रायकवार कौन है? जिन्हें 'अनसंग हीरोज' (Unsung Heroes) की श्रेणी में राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजेंगी। उनके बार में विस्तार से जानिए।

बुंदेलखंड की पारंपरिक अखाड़ा संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले 83 वर्षीय गुरु भगवानदास रायकवार को 'पद्मश्री सम्मान 2026'से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान उन्हें भारतीय पारंपरिक 'मार्शल आर्ट' और 'अखाड़ा विद्या' के संरक्षण, संवर्धन और प्रशिक्षण में योगदान के लिए दिया जा रहा है। उन्होंने न सिर्फ अखाड़ा कला का संरक्षण किया, बल्कि इसे नई पीढ़ी में भी आगे बढ़ाया है।

अखाड़ा की युद्ध कला को नई पीढ़ी तक पहुंचाया

भगवानदास रायकवार 'श्री छत्रसाल बुंदेलखंड अखाड़ा के संचालक' हैं। वे पिछले कई दशकों से अखाड़ा, लाठी, भाला, तलवार, त्रिशूल, फरसा जैसी प्राचीन युद्ध कलाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में आयोजित राष्ट्रीय व सांस्कृतिक आयोजनों में भारतीय परंपरा का गौरव बढ़ाया है।

राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कला को स्थान दिलाया

अखाड़ा गुरु भगवानदास रायकवार महाकुंभ, लोक रंग, सूरजकुंड मेला, राष्ट्रीय नाट्य एवं सांस्कृतिक महोत्सवों में निरंतर सहभागिता करते रहे हैं। वर्ष 2025 में प्रयागराज महाकुंभ, भोपाल, उज्जैन और अयोध्या में आयोजित प्रमुख आयोजनों में भी उन्होंने अखाड़ा कला का प्रदर्शन किया। उनको पद्मश्री सम्मान की घोषणा से बुंदेलखंड कला, संस्कृति और अखाड़ा जगत से जुड़े लोगों में खुशी की लहर है।

सागर में चाकू से हमला करने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया

• सागर, प्रतिनिधि

महेंद्र पाण्डेय जिला संवाददाता | सागर। गोपालगंज थाना पुलिस द्वारा बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (बीएमसी) सागर परिसर में घटित गंभीर चाकूबाजी की घटना में फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की गई है।

पुलिस के अनुसार - बीएमसी परिसर में घटित आपराधिक घटनाओं के क्रम में यह तीसरा बड़ा मामला है, जिसमें गोपालगंज पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिससे क्षेत्र में अपराधियों में भय एवं आमजन में विश्वास का वातावरण बना है।

दिनांक 19.01.2026 को थाना गोपालगंज क्षेत्र अंतर्गत बीएमसी सागर के इमरजेंसी वार्ड के सामने फरियादी अमोल यादव, पिता रामेश्वर यादव, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम रसल्ला, थाना बहेरिया, जिला सागर के साथ आरोपियों द्वारा शराब के नशे में गाली-गलौज कर मारपीट की गई। इसी दौरान आरोपी गोलू रैकवार द्वारा फरियादी पर चाकू से कई बार जानलेवा हमला किया गया, जिससे फरियादी को गंभीर चोटें आईं और तत्काल चिकित्सकीय उपचार कराना पड़ा।

घटना के बाद आरोपी तन्नु रैकवार एवं गोलू रैकवार, दोनों निवासी मनोरमा कॉलोनी, गोपालगंज, मौके से फरार हो गए थे। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना गोपालगंज में

अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरुद्ध धारा 296-ए, 115(2), 118(1), 110, 351(2), 3(5) बी.एन.एस. के अंतर्गत विवेचना प्रारंभ की गई।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक श्री घनश्याम शर्मा द्वारा विशेष पुलिस टीम गठित की गई। दिनांक 28.01.2026 को खुफिया तंत्र एवं तकनीकी माध्यमों से सूचना प्राप्त हुई कि दोनों फरार आरोपी शहर में प्रवेश करने वाले हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मनोरमा कॉलोनी के सामने स्थित यूटीडी के जंगल क्षेत्र से दोनों आरोपियों को घेराबंदी कर दबोच लिया।

पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू जप्त किया गया है तथा आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही जारी है।

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम - उप निरीक्षक नीरज जैन, सउनि राजेश चौबे, प्रधान आरक्षक दीपक व्यास, आरक्षक देवेन्द्र पाण्डेय, आरक्षक अंकित तिवारी एवं आरक्षक दशरथ मालवीय। बीएमसी जैसे संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण संस्थान में लगातार अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं त्वरित गिरफ्तारी यह दर्शाती है कि सागर पुलिस अपराधियों के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति के साथ कार्य कर रही है।

मालथौन चेक पोस्ट पर ट्रक चालकों का तांडव, सरकारी वाहन पर किया पथराव, आगजनी की कोशिश

• सागर, प्रतिनिधि

सागर | मप्र-उप्र की सीमावर्ती चेक पोस्ट पर ट्रक चालकों ने दस्तावेजों की जांच के दौरान हंगामा खड़ा कर दिया। ट्रक चालकों ने आरटीओ टीम द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर लगाए गए जुर्माने को लेकर कर्मचारियों के साथ गाली-गालौज की और वहां मौजूद वाहन पर पथराव कर दिया।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित अटा आरटीओ चेक पोस्ट सोमवार को रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। दस्तावेजों की जांच से नाराज ट्रक चालकों ने सरकारी कार्य में बाधा डाली और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों से बदसलूकी करने का प्रयास किया। उग्र भीड़ ने सरकारी वाहन पर पथराव कर उसके कांच तोड़ दिए और चेक पोस्ट पर बनी अस्थायी झोपड़ी में आग लगाने की कोशिश की।

चेकिंग से भड़के ड्राइवर - चेक पोस्ट प्रभारी कुलदीप भार्गव ने बताया कि सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच कुछ ट्रक चालकों को दस्तावेज जांच के लिए रोका गया था। जांच के दौरान दो ट्रकों के कागजात अधूरे पाए गए, जिस पर आरटीओ टीम ने जुर्माना लगा दिया। इनमें ट्रक क्रमांक UK 06 CB 5081 पर 40,000 रुपये का जुर्माना और ट्रक क्रमांक HR 67 E 3129 पर 31,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस कार्रवाई से नाराज चालकों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और देखते ही देखते पथराव करने लगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि उग्र भीड़ ने मौके पर खड़ी सरकारी गाड़ी को निशाना बनाया। एक चालक ने तिरपाल से बनी झोपड़ी में आग लगाने की कोशिश की, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्टाफ ने किसी तरह अपनी जान बचाई।

चेक पोस्ट कर्मचारियों के अनुसार इस मार्ग पर ट्रक चालकों द्वारा उपद्रव की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बीते छह महीनों में यह चौथी बड़ी घटना है। नवंबर में एक चालक ने नशे की हालत में ट्रक पलटकर चक्काजाम कर दिया था। हाल ही में आरटीओ ने नशे में वाहन चलाने वाले पांच चालकों के लाइसेंस निलंबित किए हैं।

अधिकारियों का कहना है कि उपद्रव करने वाले चालकों की पहचान की जा रही है। पुलिस में सरकारी कार्य में बाधा डालने और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया जा रहा है।

पैसे देकर MBBS में बच्चों को दिलाना चाहते हैं एडमिशन, तो पहले इस खबर को पढ़ लें, कैसे-कैसे लगाया जा रहा है चूना

आरोपी के झांसे में आकर फरियादी ने अलग-अलग किश्तों में कुल 28 लाख 75 हजार रुपए उसे दे दिए. परिवार को उम्मीद थी कि जल्द ही बेटे का मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो जाएगा, लेकिन समय बीतता गया और आरोपी टालमटोल करता रहा.

• सागर, प्रतिनिधि

सागर | सागर जिले के मोतीनगर थाना क्षेत्र में मेडिकल एडमिशन के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. आरोपी ने खुद को वकील और प्रभावशाली लोगों से जुड़ा बताकर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से लाखों रुपये ऐंठ लिए. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

पीड़ित माधव गोविंद गुप्ता, जो पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं. उन्होंने पुलिस को बताया कि उनका बेटा वर्ष 2022 में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था. इसी दौरान उनकी मुलाकात दवा लेने आने वाले रामकुमार उपाध्याय से हुई. बातचीत के दौरान आरोपी ने खुद को वकील बताते हुए मेडिकल कॉलेजों में मजबूत संपर्क होने का दावा किया. साथ ही उसने भरोसा दिलाया कि वह कई छात्रों को पहले भी एमबीबीएस में एडमिशन दिला चुका है. लिहाजा, वह उनके बेटे का भी दाखिला करवा सकता है. इस काम के लिए उसने 25 से 30 लाख रुपये खर्च होने की बात कही.

किस्तों में दिए गए 28.75 लाख रुपये

आरोपी के झांसे में आकर फरियादी ने अलग-अलग किश्तों में कुल 28 लाख 75 हजार रुपए उसे दे दिए. परिवार को उम्मीद थी कि जल्द ही बेटे का मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो जाएगा, लेकिन समय बीतता गया और आरोपी टालमटोल करता रहा. इसी बीच युवक ने अच्छे अंक हासिल कर अपने दम पर नियमानुसार मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पा लिया. इसके बाद जब परिवार ने आरोपी से अपनी रकम लौटाने को कहा, तो उसने साफ इंकार कर दिया.

पुलिस तक पहुंचा मामला, आरोपी गिरफ्तार

अपने साथ हुई ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने मोतीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया. तकनीकी साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर रामकुमार उपाध्याय को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

इस पूरे मामले पर सीएसपी ललित कुमार कश्यप ने बताया कि हो सकता कि आरोपी ने और भी लोगों को इसी तरह झांसा दिया होगा. मामले की विस्तृत जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ठगी का दायरा कितना बड़ा है.

सागर के शासकीय प्राथमिक शाला गढ़ौली की ढही छत, एक छात्र घायल, लहूलुहान हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती

घायल छात्र के पिता रामकेश बंसल ने बताया कि स्कूल से फोन कर उन्हें बेटे के घायल होने की सूचना दी गई. काम छोड़कर जब वो स्कूल पहुंचे तो देखा कि उनका बेटा बुरी तरह जख्मी था और उसके सिर से खून बह रहा था. इसके बाद परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे.

• सागर, प्रतिनिधि

सागर | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर किए जा रहे दावों की पोल खोलने वाली एक गंभीर घटना सागर जिले से सामने आई है. खुरई रोड स्थित शासकीय प्राथमिक शाला गढ़ौली खुर्द में जर्जर भवन की छत का प्लास्टर गिरने से दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला 8 वर्षीय छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया. बच्चे के सिर में गहरी चोट आई है, जिसे उपचार के लिए सागर के भाग्योदय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों द्वारा जटिल ऑपरेशन किया जा रहा है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

पढ़ाई के दौरान अचानक गिरा छत का प्लास्टर

जानकारी के अनुसार, यह घटना सुबह करीब 11 बजे की है. कक्षा में पढ़ाई के दौरान अचानक छत से प्लास्टर गिरने के कारण अफरा-तफरी मच गई. स्कूल प्रबंधन द्वारा सभी बच्चों को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन इसी दौरान घायल छात्र का कुछ सामान कक्षा में रह गया. जब वह दोबारा सामान लेने कक्षा में गया, तभी छत की सीलिंग से प्लास्टर का बड़ा टुकड़ा उसके सिर पर गिर गया.

एक छात्र गंभीर रूप से घायल

घायल बच्चे के पिता रामकेश बंसल ने बताया कि स्कूल से फोन कर उन्हें बेटे के घायल होने की सूचना दी गई. काम छोड़कर जब वे स्कूल पहुंचे तो देखा कि उनका बेटा बुरी तरह जख्मी था और उसके सिर से खून बह रहा था. इसके बाद परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे.

यह घटना महज एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सरकारी स्कूलों की भवन सुरक्षा और रखरखाव व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है. इससे पहले भी प्रदेश के कई जिलों में जर्जर स्कूल भवनों से जुड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं होने से ऐसे हादसे लगातार दोहराए जा रहे हैं.

गरीब और कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में इस भरोसे के साथ भेजते हैं कि वहां उन्हें सुरक्षित वातावरण मिलेगा, लेकिन सागर से सटे क्षेत्र में स्थित इस स्कूल की जर्जर हालत ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं.

अब देखना यह होगा कि शिक्षा विभाग इस गंभीर मामले को कितनी संवेदनशीलता से लेता है, जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है और भविष्य में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं, या फिर यह मामला भी कागजी जांच तक सीमित रह जाएगा.

सवालों के घेरे में सरकारी स्कूलों की सुरक्षा

सरकारी स्कूलों को लेकर सरकारी विज्ञापनों में बेहतर भवन, सुरक्षित कक्षाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन गढ़ौली खुर्द प्राथमिक शाला की यह घटना उन दावों की सच्चाई उजागर करती है. सवाल सिर्फ यह नहीं है कि छत का प्लास्टर क्यों गिरा, बल्कि यह है कि जर्जर भवन में मासूम बच्चों को पढ़ने के लिए क्यों बैठाया गया. इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद कुमार जैन से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन वे कार्यालय में उपस्थित नहीं मिले. फोन पर संपर्क करने पर उन्होंने किसी बैठक में व्यस्त होने की बात कहकर कॉल काट दिया.

यूजीसी के खिलाफ हुए सवर्ण छात्र, 'काला कानून' वापस लेने की मांग

डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ छात्रों का विरोध तेज हो गया है. छात्रों का कहना है कि यह नियम शिक्षकों और छात्रों दोनों पर अनावश्यक दबाव डालेगा और शिक्षा माहौल पर नकारात्मक असर पड़ेगा.

• सागर, प्रतिनिधि

सागर | डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर में यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है. सवर्ण छात्र इसे 'काला कानून' बताया है. उनका कहना है कि यह नियम छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए समस्याएं खड़ी करेगा और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए. बढ़ते विरोध को देखते हुए यह मामला अब और गंभीर होता दिख रहा है.

यूजीसी के नियम के खिलाफ छात्र एकजुट

विरोध कर रहे छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में नारेबाजी की और नए नियम को पूरी तरह से अव्यावहारिक बताया. उनका कहना है कि यह निर्देश न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को कमजोर करता है और छात्रों की स्वतंत्रता पर सीधा असर डालता है. छात्रों ने कहा कि इस तरह के फैसले बिना व्यापक चर्चा के नहीं लिए जाने चाहिए.

ब्लैकमेलिंग और फर्जी शिकायतों का डर

छात्रों का आरोप है कि यूजीसी के इस नियम से फर्जी शिकायतें बढ़ने की आशंका है. उनका कहना है कि इससे शिक्षक-छात्र संबंधों में तनाव बढ़ेगा और कई लोग मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं. छात्रों ने इसे एक ऐसा कदम बताया है जो शिक्षा के माहौल को बिगाड़ देगा और अनावश्यक विवादों को जन्म देगा.

सरकार से नियम वापस लेने की मांग

छात्र नेताओं ने स्पष्ट कहा कि सरकार को इस नियम पर पुनर्विचार करना चाहिए. उनका सुझाव है कि सभी वर्गों के छात्रों से चर्चा कर ही कोई अंतिम फैसला लिया जाए. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और बड़े स्तर पर ले जाया जाएगा.

विश्वविद्यालय प्रशासन अब तक मौन

गौरतलब है कि इस पूरे विवाद पर अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है. छात्रों का कहना है कि प्रशासन की चुप्पी भी उनके सवालों और आशंकाओं को बढ़ा रही है. वे चाहते हैं कि विश्वविद्यालय भी इस मुद्दे पर अपनी स्पष्ट स्थिति रखे.

हत्या के दोषी ने जेल से की पोस्ट ग्रेजुएशन, साथी कैदियों को भी पढ़ाया, माफ हो गई उम्रकैद की सजा, 9 कैदी के साथ रिहा

• सागर, प्रतिनिधि

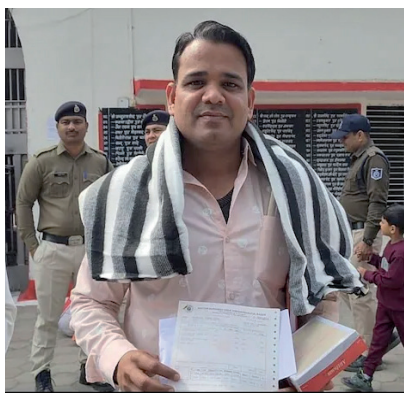

गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर केंद्रीय जेल सागर से हत्या के मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 9 कैदियों को रिहा किया गया. इन सभी कैदियों की सजा अवधि पूर्ण हो चुकी थी, जिसके बाद जेल प्रशासन द्वारा नियमानुसार उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की गई. जेल से बाहर निकलते समय कैदियों के चेहरों पर एक नए जीवन की शुरुआत की उम्मीद साफ दिखाई दी.

हत्या के मामले में काट रहे थे सजा - रिहा हुए कैदियों में सागर जिले के ग्राम बरा निवासी राजेंद्र सिंह लोधी भी शामिल हैं, जिनकी कहानी सुधार और आत्मनिर्भरता का उदाहरण बनकर सामने आई है. राजेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि वो हत्या के एक मामले में केंद्रीय जेल सागर में सजा काट रहे थे. न्यायालय द्वारा उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. जेल में बिताए गए लंबे समय के दौरान उन्होंने निराश होने के बजाय शिक्षा को अपना सहारा बनाया और अपने भविष्य को नई दिशा देने का संकल्प लिया.

जेल से की पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई - राजेंद्र ने जेल में रहते हुए डॉक्टर हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की. इसके साथ ही उन्होंने समाजशास्त्र (सोशियोलॉजी) में एमए किया और टूर एंड ट्रैवल्स मैनेजमेंट का कोर्स भी सफलतापूर्वक पूरा किया. यह सभी पढ़ाइयां उन्होंने जेल में रहते हुए कीं और अच्छे अंकों के साथ परीक्षाएं उत्तीर्ण कीं. उनका कहना है कि पढ़ाई ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाया और जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखने की प्रेरणा दी.

24 की उम्र में गए थे जेल - राजेंद्र ने बताया कि वर्ष 2011 में गांव में हुए एक विवाद के दौरान वे हत्या के मामले में जेल गए थे. उस समय उनकी उम्र मात्र 24 वर्ष थी और वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे. एक अचानक हुए विवाद ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और सरकारी नौकरी का सपना अधूरा रह गया. हालांकि जेल में रहते हुए उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई जारी रखी.

बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में थैलेसीमिया एवं सिकल सेल एनीमिया की जाँच सुविधा शुरू

• सागर, प्रतिनिधि

सागर | बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता (Dean) डॉ. पी. एस. ठाकुर द्वारा पैथोलॉजी विभाग के अंतर्गत HPLC (हाई परफॉरमेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी) मशीन का शुभारंभ किया गया। इस मशीन के माध्यम से अब जिले एवं संभाग के मरीजों को थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया एवं अन्य प्रकार के हीमोग्लोबिन विकारों की सटीक जाँच बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में ही निःशुल्क उपलब्ध होगी।

गौरतलब है कि बाजार में इस जाँच का मूल्य 1000 रुपये से 1500 रुपये के बीच है। इस अवसर पर अस्पताल अधीक्षक डॉ. राजेश जैन, पैथोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. अमर गंगवानी एवं मीडिया प्रभारी डॉ. सौरभ जैन सहित विभाग के समस्त चिकित्सक, तकनीशियन एवं एच.ए.सी.एल. (HACL) के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

पैथोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. अमर गंगवानी ने बताया कि इस मशीन द्वारा हीमोग्लोबिन की कमी वाले बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं में विभिन्न रक्त विकारों की पहचान हो सकेगी, जिससे उनके उचित उपचार में बड़ी सहायता मिलेगी।

पीएम सूर्य घर योजना में अब तक 29 हजार 275 उपभोक्ताओं के खातों में पहुंची 228 करोड़ से अधिक की सब्सिडी

योजना में तीन किलोवॉट के सौर संयन्त्र लगाने पर 78 हजार की सब्सिडी मिलेगी

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में पीएम सूर्यघर योजना के तहत अब तक कुल 29 हजार 273 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं। इन्हें 228 करोड़ से अधिक की राशि सब्सिडी के रूप में उनके खातों में जमा कराई जा चुकी है। कंपनी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उपरांत विद्युत वितरण कंपनी में रजिस्टर्ड अधिकृत वेंडर से ही सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाएं। देश के करोड़ों घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीएम सूर्य घर योजना प्रारंभ की गई है। लोगों को इस योजना का लाभ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत एक किलोवॉट सोलर संयन्त्र लगाने पर 30 हजार रुपए, दो किलोवॉट सोलर संयन्त्र लगाने पर 60 हजार रुपए तथा तीन किलोवॉट या उससे अधिक के सोलर संयन्त्र स्थापना पर 78 हजार रुपए की सब्सिडी केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही है। गौरतलब है कि पीएम सूर्यघर योजना का शुभारंभ 13 फरवरी 2024 को हुआ था। तब से लेकर आज दिनांक तक हजारों बिजली उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ा गया है। योजना में शामिल होने के लिए आनलाइन आवेदन करना होगा। जिसके लिए पीएम सूर्य घर योजना की वेबसाइट https://www.pmsuryaghar.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। वॉट्सएप चेटबॉट व टोल फ्री नं. 1912 पर भी संपर्क किया जा सकता है। कंपनी ने कहा कि उपभोक्ताओं को समय पर सब्सिडी मिले इसके लिए वेंडर और उपभोक्ता दोनों को ध्यान रखना होगा कि उनके बैंक खाते में नाम, आधार कार्ड में नाम तथा बिजली बिल में नाम एक समान होना चाहिए। गौरतलब है कि 1 दिसंबर 2024 से स्थापित होने वाले प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत सौर संयंत्रों में केवल स्मार्ट मीटर ही लगाए जा रहे हैं, जो कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा एस.ओ.आर. रेट पर उपभोक्ताओं को प्रदान किए जा रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं द्वारा सोलर वेंडर को किए जाने वाले भुगतान में लगभग 6 से 8 हजार रुपए तक की कमी परिलक्षित हो रही है।

किसान अकेला नहीं, हम सब साथ खड़े हैं

अतिवृष्टि से फसलें बर्बाद होने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सरकार से की मुआवजा देने की मांग

भोपाल । मध्य प्रदेश में मौसम अचानक बदल गया है। ठंड के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। जिसकी वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। इसे लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सरकार से सर्वे कराने और मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम सब किसानों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस नेता व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो शेयर किया हैं। जिसमें उन्होंने लिखा- खरगोन, आगर, गुना और उज्जैन सहित अन्य जिलों में ओलावृष्टि व अतिवृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। किसान की मेहनत, उम्मीद कुछ मिट्टी में मिल गई है। सरकार से मांग है कि तत्काल सर्वे कराकर किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। किसान अकेला नहीं है, हम सब उसके साथ खड़े हैं। 20 से ज्यादा जिलों में हुई बारिश आपको बता दें कि एमपी में ठंड के मौसम में बारिश-ओले का दौर चल रहा है। मंगलवार को उज्जैन, शाजापुर, आगर-मालवा, गुना में ओले गिरे। प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। जिससे कई जगहों पर किसानों की फसलें खराब हो गई। इधर, देवास में हुई ओलावृष्टि पर कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने संज्ञान लिया। देवास कलेक्टर ने लिया संज्ञान देवास कलेक्टर ऋतुराज ने फसलों को नुकसान की जानकारी प्राप्त होने पर प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित सर्वेक्षण करने के लिए तहसीलदार की अध्यक्षता में एक दल गठित करने के निर्देश दिए हैं। इस दल को राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 6-4 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति का मामला दर्ज करने, पंचनामा तैयार करने, प्रभावित किसानों के आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया है।

राजधानी में 15 से 20 प्रतिशत तक महंगी हो सकती है प्रापर्टी

वर्ष 2026-27 की गाइडलाइन को लेकर तैयारियां शुरू, जल्द होगी उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठक

भोपाल । भोपाल जिले में एक बार फिर प्रापर्टी को 15 से 20 प्रतिशत महंगी करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसको लेकर जिलेभर में जिन स्थानों पर अधिक दामों पर रजिस्ट्रियां हुईं हैं, वहां का रिकॉर्ड पंजीयन विभाग ने राजस्व विभाग से मांगा है। इन क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों और प्रापर्टी की खरीद-फरोख्त के आधार पर ही प्रापर्टी के नए दाम तय किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठक मंगलवार को तय थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सकी है। ऐसे में अब जल्द ही बैठक आयोजित कर गाइडलाइन के प्रस्ताव को लेकर चर्चा होगी। इसको अंतिम रूप देने के बाद जिला मूल्यांकन समिति को भेज दिया जाएगा। इस तरह जिले में वित्तीय वर्ष 2026-27 की कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। नई कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर पंजीयन व राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा सर्वे किया जा रहा है। पंजीयन विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, कुछ ही दिन में प्रस्ताव तैयार हो जाएगा, जिसे उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में रखा जाएगा। जिन क्षेत्रों में तय दाम से अधिक दाम पर रजिस्ट्रियां हुई हैं, वहां पर 15 से 20 प्रतिशत तक प्रापर्टी की दाम बढ़ाए जा सकते हैं। इसके लिए राजस्व विभाग से जानकारी मांगी है। रिकॉर्ड पटवारियों से तैयार कर मांगा गया भोपाल जिले की नगरीय और ग्रामीण सीमा के क्षेत्रों में जमकर प्रापर्टी की खरीद-फरोख्त की गई हैं, ऐसे में इन इलाकों का रिकॉर्ड पटवारियों से तैयार कर मांगा गया है, जिससे पता चल सके कि यहां पर कितनी जगह पर तय दाम से अधिक दामों पर रजिस्ट्रियां हुईं हैं। अधिक दाम पर होने वाली रजिस्ट्रियों को ही दाम में वृद्धि करने का आधार बनाया जाएगा। इसके लिए हुजूर, कोलार, बैरसिया तहसील के एसडीएम, तहसीलदार द्वारा पटवारियों से सर्वे करवाकर जानकारी जुटाई जा रही है। इन इलाकों में जमकर हो रही प्रापर्टी की खरीद फरोख्त भोपाल जिले के कटारा हिल्स, अवधपुरी, खजूरी कलां, 11 मील, सहारा एस्टेट, सलैया, मिसरोद, समरधा, कोलार, नर्मदापुरम रोड, रातीबड़, नीलबड़, मुगालिया छाप, ईंटखेड़ी छाप, फंदा, खजूरी सडक, भैंसाखेड़ी, कोलूखेड़ी, परवलिया सडक, चंदूखेड़ी, गांधीनगर, जेल रोड, अयोध्या बायपास, आनंद नगर, बिलखिरिया, रायसेन रोड, कान्हासैया, ओंकारा सेवनियां, सूखी सेवनियां, भोपाल बायपास, जगदीशपुर, ईंटखेड़ी, लांबाखेड़ा, करोंद, पलाशी, मुबारकपुर, डोबरा, परेवाखेड़ा, अचारपुरा, पुरामनभावन, देवलखेड़ी, गोलखेड़ी, श्यामपुर सहित नगरीय व ग्रामीण सीमा में प्रापर्टी की खरीदी हो रही है।

उज्जैन में 100 एकड़ में बनेगा फूलों का मेगा क्लस्टर

सिंहस्थ को लेकर उद्यानिकी विभाग की तैयारी; 30 जनवरी को भोपाल में फ्लॉवर एग्जीबिशन

भोपाल। सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने उज्जैन में 100 एकड़ जमीन पर फूलों का विशेष उत्पादन क्लस्टर विकसित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर यह क्लस्टर धार्मिक नगरी उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में फूलों की बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ-साथ किसानों को स्थायी आय का साधन देगा। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने बताया कि उज्जैन, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर साल भर फूलों की बड़ी मांग रहती है। इसी को देखते हुए सरकार ने उज्जैन के आसपास व्यावसायिक पुष्प उत्पादन क्लस्टर विकसित करने की कार्य योजना बनाई है। मंत्री कुशवाह ने कहा कि सिंहस्थ मेले के दौरान करोड़ों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं और पूजा-अर्चना के लिए फूलों की मांग कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में बाहर से फूल मंगाने की बजाय स्थानीय किसानों द्वारा उत्पादित फूलों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इससे परिवहन लागत घटेगी और किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे। किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस क्लस्टर के माध्यम से उज्जैन और आसपास के किसानों को गुलाब, गेंदा, जरबेरा, रजनीगंधा, सेवंती, ग्लेडियोलस जैसे अधिक मांग वाले फूलों की वैज्ञानिक और व्यावसायिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि पुष्प उत्पादन को केवल पारंपरिक खेती न मानते हुए कृषि-उद्यम के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मंत्री कुशवाह ने कहा कि मध्यप्रदेश पहले से ही पुष्प उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।

हज के लिए प्रतीक्षासूची से 41 यात्रियों का चयन

31 जनवरी तक जमा करनी होगी अग्रिम राशि, राज्य हज कमेटी कार्यालय में भी जमा कर सकेंगे दस्तावेज

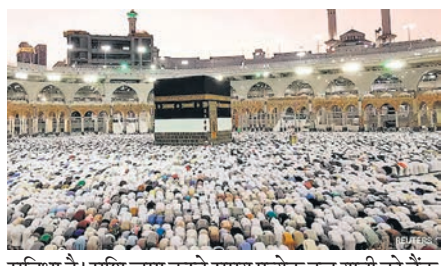

भोपाल। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज-2026 के लिए प्रतीक्षा सूची की पांचवीं सूची जारी कर दी है। इस सूची में मध्यप्रदेश की प्रतीक्षासूची क्रमांक 2968 से 3008 तक के कुल 41 हज आवेदकों को प्रोविजनल रूप से चयनित किया गया है। चयनित हज यात्रियों को अग्रिम हज राशि 2 लाख 77 हजार 300 रुपए जमा करनी होगी। इसमें प्रथम किस्त 1 लाख 52 हजार 300 रुपए और द्वितीय किस्त 1 लाख 25 हजार रुपए शामिल हैं। राशि जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तय की गई है। हज राशि हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या हज सुविधा ऐप के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से जमा की जा सकती है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में निर्धारित पे-इन-स्लिप के जरिए भी राशि जमा करने की सुविधा है। राशि जमा करते समय प्रत्येक हज यात्री को बैंक रेफरेंस नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा। राशि जमा करने के बाद प्रोविजनल रूप से चयनित हज यात्रियों को हज आवेदन फॉर्म की हस्ताक्षरित प्रति, आवश्यक दस्तावेज और मेडिकल स्क्रीनिंग व फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा।

किसान कल्याण स्वाभिमान पर्व क्विज का प्रथम चरण 15 मार्च तक

भोपाल । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किसानों के कल्याण, स्वाभिमान और समृद्धि के लिए संचालित योजनाओं को व्यापक जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग अंतर्गत वीर भारत न्यास एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा एक अभिनव और ऐतिहासिक पहल की है। वर्ष 2026 को किसान कल्याण स्वाभिमान पर्व के रूप में मनाते हुए प्रदेश में लोक और जनजातीय कलाओं के बहुरंगी उत्सव के साथ एक विशाल राज्य स्तरीय इनामी क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का प्रथम चरण 15 मार्च 2025 तक चलेगा। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को लगभग 6.50 करोड राशि के ट्रैक्टर, बुलेट मोटरसाइकिल, ई स्कूटर एवं अन्य आकर्षक पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे। यह जानकारी संस्कृति संचालनालय के संचालक एनपी नामदेव एवं मुख्यमंत्रीजी के संस्कृति सलाहकार एवं वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी ने प्रेस को संबोधित करते हुए दी। वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी ने बताया कि यह पहल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में किसानों को योजनाओं से जोडने, उनमें जागरूकता बढ़ाने और सम्मान का भाव सुदृढ़ करने की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगी। किसान कल्याण स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, निमाड़ और महाकौशल अंचलों में वर्ष भर लोक एवं जनजातीय कलाओं के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

45 बर्खास्त परिवहन आरक्षकों को फिर मिलेगी नौकरी

विधि विभाग की टीप के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग से मिली स्वीकृति

भोपाल। प्रदेश सरकार में नौकरशाही किस तरह से सरकार की किरकिरी कराने में जुटी है। इसका बड़ा मामला सामने आया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सरकार ने पिछले साल जिन 45 आरक्षकों को बर्खास्त किया था, उन्हें जबलपुर उच्च न्यायालय के एक आदेश के हवाले से फिर से सेवा में रखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार, जिन 45 परिवहन आरक्षकों को बर्खास्त किया था, उन्हें परिवहन, विधि और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने उच्च न्यायालय के एक आदेश का हवाला देकर फिर से नौकरी में रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। परिवहन आयुक्त कार्यालय ने बर्खास्त आरक्षकों को वापस नौकरी पर रखने का जो प्रस्ताव भेजा था। परिवहन विभाग ने बिना किसी आपत्ति के विधि विभाग भेज दिया। विधि विभाग ने भी प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को नौकरी देने की टीप लिख दी। इसके आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग से स्वीकृति मिल गई है। दरअसल, 2012 में परिवहन विभाग ने महिला पदों पर पुरुषों को नियुक्ति दे दी थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर परिवहन विभाग ने सितंबर 2024 में 45 परिवहन आरक्षकों को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद बर्खास्त आरक्षक फिर से जबलपुर उच्च न्यायालय गए। जस्टिस मिश्रा की पीठ ने यह कहकर याचिका खारिज कर दी थी कि गलत नियमों से भर्ती करने वाले अधिकारियों से इनकी 10 साल के वेतन भत्ते वसूले जाएं। इसके खिलाफ युगल पीठ में अपील की। इसमें तर्क दिया था कि विभाग ने भर्ती नियमों का पालन नहीं किया, उनकी कोई गलती नहीं थी।युगलपीठ ने महिलाओं को नौकरी देने और महिलाओं की विशेष भर्ती करने की शर्त पर बर्खास्त आरक्षकों को वापस नौकरी पर रखने के आदेश दिए। इसके बाद परिवहन आयुक्त ने प्रस्ताव बनाकर भेजा। इसके बाद परिवहन, विधि और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने भी महिलाओं के पदों पर बर्खास्त परिवहन आरक्षकों को फिर से नौकरी देने में रुचि दिखाई। जबकि उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में नियम विरुद्ध नियुक्ति देने वाले अधिकारी और महिलाओं की विशेष नियुक्ति को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। खबर है कि सामान्य प्रशासन विभाग से मंजूरी मिलने के बाद परिवहन विभाग गुपचुप तौर पर आरक्षकों को वापस नौकरी पर रखने की तैयारी में है। क्योंकि विभागीय अधिकारियों को आशंका है कि नियुक्ति आदेश से पहले मामला न्यायालय में जा सकता है। क्योंकि न्यायालय ने बर्खास्त आरक्षकों को सशर्त नौकरी पर रखने के लिए आदेश दिए थे। जिसमें से महिलाओं की नियुक्ति और अधिकारियों से वसूली शामिल है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये बर्खास्त आरक्षक होंगे बहाल जिन बर्खास्त आरक्षकों को बहाल किया जाएगा उनमें सामान्य वर्ग के श्रीनाथ शर्मा, सौरभसिंघल, अजय सिंह भदौरिया, हरिओम कुशवाह, भूपेन्द्र सिंह तोमर, नीरज शर्मा, मानवेन्द्र सिंह जादौन, कर्मवीर सिंह, शैलेन्द्र सिंह राजपूत, सुखदेव शर्मा, महेन्द्र जरिया, राकेश तोमर, दीपेन्द्र सक्सेना, मनीष खरे, नरेन्द्र चतुर्वेदी, शुभम शर्मा, शिवकुमार गुप्ता, रोहित कुमार दुबे, रूपेश कटारे, राहुल कुशवाह, राघवेन्द्र तिवारी, कमलेश तिवारी, शशांक द्विवेदी, कुलदीप गुप्ता, नितिन कुमार मिश्रा, प्रखर पांडे, पुष्पेन्द्र सिंह बुंदेला, अनुराग सिंह भदौरिया, जितेन्द्र सिंह सेंगर, विनय सारस्वत, कमल प्रताप सेंगर, रावेन्द्र मिश्रा शामिल हैं। वहीं ओबीसी वर्ग से सुमन सूर्यभान लोधी, शिशिर रैकवार, प्रेमनारायण कुशवाह, राजकुमार गुर्जर, सुनील साहू, अजय सिंह दांगी, जितेन्द्र सिंह, अरुण यादव, नितिन चौधरी, विचित्र सिंह किरार, विकास पटेल और अजजा वर्ग से राम सजीवन बैगा, सुनील सिंह वास्कले शामिल हैं।

मजबूत परिवार, सशक्त समाज की दिशा में निर्णायक पहल

भोपाल। महिला बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के मार्गदर्शन में विवाह-पूर्व संवाद को संस्थागत स्वरूप देने वाली देश की पहली संरचित पहल तेरे मेरे सपने के अंतर्गत प्री-मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर का शुभारंभ भोपाल में किया। इस अवसर पर उन्होंने शक्ति सदन का भी शुभारंभ किया। मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा कि जब तेरे और मेरे सपने मिलकर हमारे सपने बनते हैं, तभी एक स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त भारत का निर्माण संभव है। मजबूत समाज की नींव मजबूत परिवार होते हैं और मजबूत परिवार सोच-समझकर बनाए गए रिश्तों से ही संभव हैं। उन्होंने कहा कि आज के बदलते सामाजिक परिदृश्य में विवाह से पहले संवाद, समझ भावनात्मक तैयारी अत्यंत आवश्यक हो गई है। तेरे मेरे सपने पहल युवाओं को विवाह से पूर्व आपसी अपेक्षाओं, मूल्यों, जिम्मेदारियों और भविष्य की योजनाओं पर खुलकर चर्चा करने का सुरक्षित एवं मार्गदर्शित मंच प्रदान करती है। मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि संवाद की कमी, अवास्तविक अपेक्षाएँ और भूमिका स्पष्टता के अभाव में कई वैवाहिक रिश्ते तनाव, मानसिक उत्पीड़न और घरेलू हिंसा तक पहुँच जाते हैं। ऐसे में प्री-मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर न केवल विवादों की रोकथाम में सहायक होंगे, बल्कि सम्मान, सहमति और समानता पर आधारित रिश्तों को भी मजबूत बनाएंगे। उन्होंने बताया कि निर्भया फाउंडेशन द्वारा संचालित यह परियोजना महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और सशक्तिकरण के राष्ट्रीय संकल्प को मजबूती प्रदान करती है। विवाह से पहले स्पष्टता और संवाद घरेलू हिंसा एवं पारिवारिक विवादों की संभावनाओं को प्रभावी रूप से कम कर सकते हैं।मंत्री सुश्री भूरिया ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती विजया राहटकर के प्रति आभार व्यक्त किया, जिनके मार्गदर्शन में इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए भोपाल का चयन किया गया।अभियान से जुड़ी डॉ. प्रतिभा राजगोपाल के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रशासनिक प्रशिक्षण अनुभव से इस पहल को व्यावहारिक और सशक्त दिशा मिलेगी। उन्होंने समाज के अध्यक्षों, धर्मगुरुओं, अभिभावकों और युवाओं से आग्रह किया कि वे विवाह को केवल सामाजिक औपचारिकता नहीं, बल्कि समझदारी और साझेदारी का निर्णय बनाएं तथा विवाह से पूर्व संवाद को स्वीकार करें।

उन्नति पैनल को मिल रहा व्यापारिक संगठनों का पुरजोर समर्थन

टी टी नगर में सघन जनसंपर्क के साथ एमपी नगर व्यापारियों संगठनों के साथ हुई बैठक और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा

भोपाल। राजधानी के व्यापारियों की प्रतिष्ठित संस्था चेंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में उन्नति पैनल को राजधानी के व्यापारिक संगठनों को समर्थन मिल रहा है। आज हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी गोविंद गोयल और सभी प्रत्याशियों ने नए भोपाल के टी टी नगर क्षेत्र में शहर जनसंपर्क के दौरान व्यापारिक संगठनों और व्यापारियों ने उसका भरपूर स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर महाराणा प्रताप नगर के व्यापारियों की बैठक में व्यापारियों ने पैनल के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी गोविंद गोयल से चर्चा की। जिसमें श्री गोयल ने कहा चुनाव के बाद कम से कम 10000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखेंगे और मास्टर प्लान के संबंध में भी सभी से चर्चा करेंगे। एमपी नगर क्षेत्र के प्रमुख व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी के साथ उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी द्वय आदित्य जैन मनिया, अमित गोयल, अरविंद जैन सुपारी महामंत्री पद के प्रत्याशी विनोद जैन एमपीटी ,मंत्री पद के लिए अजय देवनानी, संजीव जैन गेहूं,सुनील जैनाविन, कोषाध्यक्ष पद के लिए प्रदीप सेवानी, सह कोषाध्यक्ष पद के लिए हेमंत अग्रवाल, अतिरिक कोषाध्यक्ष अमित कुमार बिंदल, कार्यकारिणी सदस्य के लिए वात्सायन जैन, सोनू भाभा, अभिषेक जैन आदित्य, महेश सिंघई, अखिलेश मित्तल, अनिल मिश्रा, अमित जैन सी एस, भारत गुप्ता, दीपक दुबे, जवाहर कोटवानी, कमल भंडारी, कृष्ण गोपाल मुखारिया, मनोज कुमार साहू, राजीव साहू, डब्बू राजेश गुप्ता, मधुरम, सचिन जैन, स्मित जैन, बी आर सुलभ, मित्तल, तेजेंद्र चावला आदि मौजूद थे।

|| संपादकीय ||

कनाडा के प्रधानमंत्री की स्वदेशी अपनाने की अपील का संदेश

कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपने देश के नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की है। ट्रंप प्रशासन द्वारा कनाडाई उत्पादों पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने की धमकी को देखते हुए ये अपील की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि वह चीन के साथ व्यापार समझौता करता है तो वह कनाड़ा पर सौ फीसदी टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप की इस चेतावनी के बाद एक वीडियो संदेश में कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने देशवासियों से स्वदेशी उत्पाद अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 'कनाडा की अर्थव्यवस्था पर बाहरी दबाव है। ऐसे में कनाडा के लोगों के पास यही रास्ता है कि वो ही सामान खरीदें, जो कनाडा में बने हों। दूसरे देश क्या करते हैं, हम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। जो हमारे नियंत्रण में है उसपर फोकस करें। हम ही कनाडा के सबसे अच्छे ग्राहक हैं और हमें कनाडा में बने उत्पाद खरीदने चाहिए ताकि देश को मजबूत बनाया जा सके। अमेरिका और कनाडा दोनों देशों के बीच ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद तल्खी तब और बढ़ गई जब ट्रंप ने कई बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कही, हालांकि पिछले साल कार्नी ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि कनाडा बिकाऊ नहीं है।

आज जो हालात कनाडा के साथ हैं, वही दुनिया के कई अन्य देशों के साथ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कभी भारत तो धमकी देते हैं तो कभी चीन को। ग्रीनलैंड का समर्थन करने वाले देशों को भी इस तरह की उनकी हाल में धमकी आई है। इस तरह की धमकी एक व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा है। बड़ी शक्तियों छोटी शक्ति और देशों को दबाकर रखना चाहती हैं। वे छोटे और सम्प्रभू देशों को अपना गुलाम बनाकर रखना पसंद करती है। अपने पर निर्भर बनाए रखना चाहती है। इस तरह के आसन्न खतरे को भारत ने पहले ही भांप लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी समय से स्वदेशी अपनाने पर वैसे ही नही जोर दे रहे। भारत में स्वदेशी का विचार कोई नया नहीं है। यह हमारी राष्ट्रीय चेतना का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विचार को आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से नया आयाम दिया है। वोकल फॉर लोकल का नारा देते हुए उन्होंने देशवासियों से भारतीय उत्पादों को अपनाने और उन्हें वैश्विक बनाने का आह्वान किया है। यह दृष्टिकोण केवल आर्थिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौरव और आत्मसम्मान से भी जुड़ा हुआ है। जब हम अपने देश में बने उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं, तो हम न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करते हैं। दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम होगी। उनका हम पर दबाव कम होगा।

स्वदेशी की अवधारणा को समझने के लिए हमें महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन को याद करना होगा। गांधीजी ने स्वदेशी को केवल आर्थिक रणनीति के रूप में नहीं देखा था, बल्कि इसे स्वराज और आत्मनिर्भरता के व्यापक दर्शन का हिस्सा माना था। उनका मानना था कि जब तक हम आर्थिक रूप से परतंत्र रहेंगे, तब तक वास्तविक स्वतंत्रता संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और चरखे से बने खादी को अपनाने पर जोर दिया। गांधीजी के लिए चरखा केवल कपड़ा बनाने का साधन नहीं था, बल्कि यह आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक था।

दरअसल अंग्रेजों के शासन से पहले जरूरत का सारा सामान हमारे यहां गांव–गांव और आसपास में पैदा होता हैं। जरूरत का काफी सामान हम अपने घर तैयार कर लेते थे। अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को बड़ेबड़े उद्योग लगाकर खत्म कर दिया।

महात्मा गांधी ने स्वदेशी का महत्व समझा। उनका स्वदेशी आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हथियार बना। उन्होंने लोगों को समझाया कि जब हम विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, तो हम न केवल अपने देश की संपत्ति को बाहर भेज रहे हैं, बल्कि अपने कारीगरों और श्रमिकों को भी बेरोजगार कर रहे हैं। उनका मानना था कि प्रत्येक भारतीय को अपने गांव और अपने देश में बनी वस्तुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह विचार इतना प्रभावशाली था कि लाखों भारतीयों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और खादी को अपनाया। यह आंदोलन केवल आर्थिक नहीं था, बल्कि इसने राष्ट्रीय चेतना को जगाने और लोगों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आज की वैश्वीकृत दुनिया में स्वदेशी की अवधारणा नए अर्थ और महत्व प्राप्त कर रही है। कनाडा पर ट्रंप की टैरिफ धमकी यह दर्शाती है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार कितना अनिश्चित और राजनीतिक रूप से प्रभावित हो सकता है। जब कोई देश किसी दूसरे देश पर आर्थिक दबाव बनाना चाहता है, तो व्यापार शुल्क एक प्रमुख हथियार बन जाता है। ऐसी स्थिति में जो देश अपनी घरेलू उत्पादन क्षमता को मजबूत रखते हैं, वे बेहतर तरीके से इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। यही कारण है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपने नागरिकों से देश में बने उत्पादों को खरीदने का आग्रह किया है।

भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल इसी दिशा में एक व्यापक और दूरदर्शी कदम है। इस अभियान का उद्देश्य केवल आयात को कम करना नहीं है, बल्कि भारत को विनिर्माण, नवाचार और तकनीकी विकास का एक वैश्विक केंद्र बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने बार-बार कहा है कि आत्मनिर्भरता का अर्थ आत्मकेंद्रित होना नहीं है, बल्कि यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक विश्वसनीय और मजबूत भागीदार बनना है। जब भारतीय उत्पाद गुणवत्ता और नवाचार में उत्कृष्ट होंगे, तो वे न केवल घरेलू बाजार में सफल होंगे बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी जगह बनाएंगे।

स्वदेशी को अपनाने का अर्थ यह नहीं है कि हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार या वैश्वीकरण के खिलाफ हैं। बल्कि यह एक संतुलित दृष्टिकोण है जो घरेलू उद्योगों को मजबूत करते हुए वैश्विक बाजार में भागीदारी को भी बढ़ावा देता है। जब हमारे उद्योग मजबूत होंगे, तो हम बेहतर शर्तों पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भाग ले सकेंगे। यही कारण है कि भारत मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से घरेलू उत्पादन और नवाचार को बढ़ावा दे रहा है।

स्वदेशी उत्पादों को अपनाने से रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब हम स्थानीय उत्पाद खरीदते हैं, तो हम अपने देश के कारीगरों, किसानों, छोटे व्यवसायियों और उद्यमियों की आजीविका का समर्थन करते हैं। भारत जैसे देश में जहां बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। छोटे और मध्यम उद्योग जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, तभी फल-फूल सकते हैं जब उन्हें पर्याप्त घरेलू बाजार मिले।

स्वदेशी को सफल बनाने के लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। जब हम खरीदारी करते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि वह उत्पाद कहां बना है और किसके द्वारा बनाया गया है। छोटे निर्णय जैसे स्थानीय बाजार से खरीदारी करना, हस्तशिल्प को बढ़ावा देना, और भारतीय ब्रांड्स को चुनना, सामूहिक रूप से बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। यह केवल आर्थिक निर्णय नहीं है, बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी का प्रश्न है।

- अशोक मधुप

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

'एक भारत, एक कानून' की नीतिगत कसौटी के सियासी निहितार्थ

विभिन्न तरह के पारस्परिक विरोधाभासों से जूझ रहे भारतीय गणतंत्र के लिए 'एक भारत, एक कानून' की अवधारणा बदलते वक्त की मांग है। इसलिए इसको सरजमीं पर उतरना बेहद जरूरी है। सवाल है कि जब एक मतदाता, एक वोट का विधान सफल हो सकता है तो फिर एक भारत, एक कानून का विधान क्यों नहीं? इस बात में कोई दो राय नहीं कि ऐसी सकारात्मक कोशिशें अंततोगत्वा समतामूलक समाज की दिशा में निर्णायक साबित हो सकते हैं।

लिहाजा यदि भारतीय संविधान के संघीय ढांचे और अन्यान्य विविधताओं को बनाए रखने वाले नानाविध प्रावधानों से 'एक देश, एक कानून' की पावन और समदर्शी सोच टकराती है तो ऐसे किसी भी टकराव को नजरअंदाज कीजिए और एक समान नागरिक संहिता (UCC) या एकसमान कानूनी व्यवस्था की दिशा में एक यथार्थपरक व्यवहारिक कदम उठाइए। इससे दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, सवर्ण जैसे निरर्थक भेद भी मिटेंगे और राष्ट्र को अप्रत्याशित मजबूती मिलेगी।

यह ठीक है कि इस राह में कई संरचनात्मक बाधाएं हैं, लेकिन राष्ट्र के दूरगामी भविष्य के लिए इन कपोलकल्पित बाधाओं, वैधानिक जटिलताओं से निबटना भी तो सकारात्मक और आशावादी नेतृत्व की पहचान होती है। खासकर मोदी हैं तो मुमकिन है, वाली सोच यहां भी चरितार्थ की जा सकती है। योगी हैं तो यकीन भी किया जा सकता है। शाह हैं तो चिल्लपों भी नहीं मचेगा, ऐसा जनविश्वास है।

जहां तक संघीय ढांचे की चुनौतियों की बात है तो भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का त्रिपक्षीय विभाजन (केंद्र, राज्य, समवर्ती) एक देश, एक कानून की राह का एक बड़ा रोड़ा समझा जाता है। उदाहरणतया पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि जैसे विषय राज्य सूची में हैं, जिनमें केंद्र का सीधा हस्तक्षेप संभव नहीं होगा बिना संशोधन के। क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 246 इस विभाजन को मजबूत बनाता है, जो एकसमान कानून लागू करने में राज्यों की सहमति या संविधान संशोधन की मांग करता है।

वहीं, मौलिक अधिकारों का टकराव भी संभाव्य है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 25-28 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, जो व्यक्तिगत कानूनों (पर्सनल लॉ) को संरक्षण प्रदान करते हैं। वहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अनुच्छेद 44 के नीति-निर्देशक तत्व के रूप में रखा गया है, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है और मौलिक अधिकारों से टकरा सकता है। यही वजह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे लागू करने पर जोर दिया है (जैसे शाह बानो मामले में), लेकिन संघीय विविधता और अल्पसंख्यक अधिकारों के नाम पर राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी इस राह की सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है।

वहीं, व्यावहारिक और न्यायिक अड़चनों की बात भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकीकृत न्यायपालिका (अनुच्छेद 214) होने के बावजूद, राज्यों में उच्च न्यायालयों की स्वायत्तता और लंबित मामलों (5 करोड़ से अधिक) की भारी संख्या एकसमान कानून के कार्यान्वयन को जटिल बनाती है। इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की प्रक्रिया में राज्यों की सहमति जरूरी हो सकती है, जो राजनीतिक मतभेदों से अवरुद्ध रहती है।

जहां तक संभावित प्रभाव की बात है तो ये अड़चनें वास्तव में संविधान की विविधता-समर्थक भावना को दर्शाती हैं, जो एकता के साथ बहुलवाद को संतुलित रखती हैं। हालांकि, डिजिटल युग में एकसमान कानून आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन बिना व्यापक सहमति के यह संघीय तनाव भी पैदा कर सकता है। इसलिए केंद्र सरकार और उसकी राज्य सरकारों को इस बाबत आम सहमति तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक भारत, एक कानून में ही न केवल देश, बल्कि दुनिया का भी हित निहित, अंतर्निहित है।

देखा जाए तो समान नागरिक संहिता, भारतीय संविधान की मौलिक व्यवस्था पर ज्यादातर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, खासकर समानता के अधिकार को मजबूत करके, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता जैसे क्षेत्रों में यह टकराव पैदा कर सकता है। हालांकि, धर्म के आधार पर बंटवारे के बाद यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है बल्कि राजनीतिक कमजोरी का प्रतीक है। यह ठीक है कि संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत यह नीति-निर्देशक सिद्धांत राज्य को एकसमान नागरिक कानून बनाने का प्रयास करने को कहता है, जो मौलिक अधिकारों से जुड़ता है।

जहां तक समानता अधिकारों पर प्रभाव की बात है तो यूसीसी संवैधानिक अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता) और 15 (भेदभाव निषेध) को मजबूत बनाएगा, क्योंकि यह धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों को हटाकर लैंगिक न्याय सुनिश्चित करेगा। इसी के द्वारा तीन तलाक, असमान उत्तराधिकार जैसे मुद्दों का सम्यक समाधान हो सकता है, जो महिलाओं के अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) को प्रभावित करते हैं। हालांकि, यदि गलत तरीके से लागू हुआ तो यह अल्पसंख्यकों के बीच भेदभाव का आरोप लगा सकता है।

जहां तक धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रभाव की बात है तो अनुच्छेद 25-28 धार्मिक स्वतंत्रता और प्रबंधन का अधिकार देते हैं, जो यूसीसी से टकरा सकता है क्योंकि व्यक्तिगत कानून सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं। भले ही सर्वोच्च न्यायालय ने शाह बानो और सारला मुद्गल मामलों में यूसीसी की आवश्यकता बताई, लेकिन इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न मानते हुए संतुलित किया। फिर भी जनजातीय रीति-रिवाजों वाली समुदायों पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है।

जहां तक अन्य मौलिक प्रावधानों पर यूसीसी के प्रभाव की बात है तो यूसीसी संवैधानिक अनुच्छेद 21 को सशक्त बनाएगा, क्योंकि यूसीसी पितृसत्तात्मक प्रथाओं को चुनौती देगा और न्याय प्रक्रिया को सरल करेगा। लेकिन समवर्ती सूची के विषय होने से राज्य स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है, जो संघीय ढांचे से जुड़ी मौलिक भावना को कमजोर करेगी। कुल मिलाकर, यूसीसी मौलिक अधिकारों को आधुनिक संदर्भ दे सकता है यदि सहमति-आधारित हो तो।

यही वजह है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल के वर्षों में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर स्पष्ट निर्देश देने से इनकार किया है, बल्कि इसे संसद के क्षेत्राधिकार में माना है। भले ही कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसलों में यूसीसी के सिद्धांत का समर्थन किया, लेकिन कार्यपालिका को ही इसकी जिम्मेदारी सौंपी। जहां तक कोर्ट के रुख की बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने 2023 और 2024 में यूसीसी लागू करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया, क्योंकि यह विधायी मामला है।

भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने मार्च 2023 में छह याचिकाओं को निस्तारित करते हुए कहा कि यूसीसी संसद बनाएगी। इससे पहले आये निम्नलिखित प्रमुख फैसले में भी यूसीसी की चर्चा है। शाह बानो (1985), सरला मुदगल (1995), और जॉन वल्लामट्टम (1997) जैसे मामलों में कोर्ट ने यूसीसी की आवश्यकता पर बल दिया, लेकिन निर्देश नहीं दिए। इसी प्रकार जनवरी 2023 में उत्तराखंड यूसीसी समिति को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी खारिज हुईं।

जहां तक वर्तमान स्थिति की बात है तो जनवरी 2026 तक कोई नया निर्देश नहीं आया; क्योंकि कोर्ट यूसीसी को अनुच्छेद 44 के नीति-निर्देशक सिद्धांत के रूप में देखता है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के साथ संतुलन पर जोर देता है। यही वजह है कि भाजपा शासित उत्तराखंड सरकार ने 2024 में राज्य-स्तरीय यूसीसी लागू किया। समझा जा रहा है कि धीरे धीरे मोदी-शाह इसे पूरे देश में लागू करेंगे।

हालांकि इससे भी एक कदम आगे बढ़कर सभी जनहितकारी मामलों में यदि एक देश, एक कानून जैसे अग्रगामी प्रावधानों को लागू कर दिया जाता है तो विगत 100 सालों से अनवरत रूप से जारी फूट डालो, शासन करो की नीति का जड़मूल से खात्मा हो जाएगा। यद्यपि मुट्ठी भर चतुर सुजान विदेशी टुकड़े पर विरोध अवश्य करेंगे लेकिन जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटवाकर एक विधान, एक निशान की राष्ट्रीय नीति लागू करवा सकते हैं तो उनके लिए एक देश, एक कानून को मूर्त रूप देना-दिलवाना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते कि इस मुद्दे पर भाजपा और आरएसएस की नीति साफ और नीयत स्पष्ट हो।

- कमलेश पांडेय

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

ट्रंप के चापलूसों का बोर्ड

अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस 'बोर्ड ऑफ पीस' (शांति बोर्ड) की स्थापना का प्रयास किया है, उसमें अभी तक वे 19 देश शामिल हुए हैं, जो अमरीका की चापलूसी करने को बाध्य हैं। अलग-अलग कारणों से अमरीका के मोहताज हैं। अमरीका ही उन्हें सुरक्षा की गारंटी देता है और वह ही आर्थिक मदद करता है। उन 19 में से 12 देश इस्लामिक हैं। उनमें पाकिस्तान ने भी 'शांति बोर्ड' की सदस्यता के लिए दस्तखत किए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जब प्रारूप पर दस्तखत किए, तो सीडीएफ आसिम मुनीर भी सामने बैठे थे। अब इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान में 'जेहाद' के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। इसके कुछ खास कारण हैं। पाकिस्तान अभी तक इजरायल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देता। वह फिलिस्तीन का समर्थक रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान के 4000 फौजियों को गाजा क्षेत्र में इजरायल सेना के नेतृत्व में काम करना पड़ेगा। ट्रिगर इजरायल के हाथ में होगा और लडऩे-मरने वाले मुस्लिम फौजी होंगे। पाकिस्तान के मुस्लिम फौजियों को फिलिस्तीन, गाजा, हमास के मुसलमानों पर ही गोली चलानी पड़ेगी। जाहिर है कि मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल करेगा! अहम और बुनियादी कारण यह है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संसद को विश्वास में क्यों नहीं लिया? संसद की इजाजत के बिना इतना अहम फैसला कैसे ले लिया गया कि पाकिस्तान के 4000 फौजी गाजा में सक्रिय रहेंगे। उन्हें जो 1000 डॉलर प्रति का मेहनताना मिलेगा, वह 40 लाख डॉलर की राशि सीडीएफ आसिम मुनीर हासिल करेगा। फौजियों को जो देना होगा, वह हुकूमत तय करेगी। फौजी की मौत के बाद पर्याप्त मुआवजा और सम्मान राशि कितनी होगी और कौन देगा, यह अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। उस पर भी मुनीर की 'डकैत निगाहें' होंगी! पाकिस्तान में कट्टरपंथी जमात इसे 'इस्लाम-विरोधी' और 'अल्लाह-विरोधी' फैसला करार दे रही है।

खासकर सीडीएफ मुनीर के खिलाफ फतवे जारी किए जा रहे हैं। अवाम का मानना है कि शहबाज-मुनीर ने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने दंडवत आत्मसमर्पण कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान को पैसा चाहिए। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान को कर्ज देने से इंकार कर दिया है। चीन अपने उधार दिए गए कर्ज को वापस मांग रहा है। यदि आईएमएफ और विश्व बैंक से आर्थिक पैकेज की अपेक्षा करनी है, तो अमरीका ही एकमात्र सहारा है। राष्ट्रपति ट्रंप के इशारे पर ही पाकिस्तान को नया कर्ज मिल सकता है। पाकिस्तान पर फिलहाल 130 अरब डॉलर के करीब का कर्ज है। पाकिस्तान के हरेक नागरिक पर औसतन 3,63,831 पाक रुपए का कर्ज है। करीब 60 फीसदी अवाम गरीबी-रेखा के नीचे जीने को विवश है। भारत से करीब 25 गुना अधिक महंगाई पाकिस्तान में है। अवाम में जेहाद के नारों के साथ 'मुनीर की वर्दी उतारने' के नारे भी गूंज रहे हैं। 'तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान' सरीखा संगठन भडक़ उठा है और आत्मघाती हमलों की धमकियां दे रहा है। फिलहाल 'शांति बोर्ड' की सदस्यता निशुल्क है, लेकिन स्थायी सदस्यता के लिए 1 अरब डॉलर की फीस अदा करनी होगी। भारत की मौजूदा मौद्रिक स्थिति के मुताबिक, यह राशि 9100 करोड़ रुपए से अधिक बनती है। पाकिस्तान को अधिक राशि का भुगतान करना पड़ेगा। 'घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने' भूखा-नंगा पाकिस्तान इतनी रकम कैसे दे पाएगा? यानी सब कुछ अस्थायी है अभी। यदि विश्व-व्यवस्था के संदर्भ में इस 'शांति बोर्ड' का विश्लेषण करें, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी और वीटोधारक सदस्य देशों में से सिर्फ अमरीका ही सदस्य है। रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन समेत भारत, जर्मनी, इटली, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, पराग्वे, स्लोवेनिया, तुर्किये, यूक्रेन आदि देश न तो बोर्ड से जुड़े हैं और न ही ट्रंप के निमंत्रण का जवाब दे रहे हैं।

टेक्नोलॉजी

WhatsApp पर अनजान नंबरों से आने वाली कॉल्स ने कर लिया परेशान? यह सेटिंग कर लें ऑन, फिर नहीं बजेगा फोन

अगर आप WhatsApp पर अनजान कॉलर से आने वाली कॉल्स से परेशान है तो आसान तरीके से इससे छुटकारा पाया जा सकता है. आपको बस सेटिंग में थोड़ा-सा बदलाव करना है और अनजान कॉल्स साइलेंट हो जाएंगी.

स्पैम या अनजान नंबरों से आने वाली फोन कॉल से सभी लोग परेशान रहते हैं. कुछ लोगों के लिए व्हाट्सऐप पर भी अनजान नंबरों से बहुत कॉल्स आती हैं. अगर आप भी ऐसी समस्या परेशान हैं तो आसान तरीके से इन कॉल्स को साइलेंस कर सकते हैं. आपको बस सेटिंग में थोड़ा-सा बदलाव करना है और आपका फोन बार-बार बजना बंद हो जाएगा. आज हम आपको व्हाट्सऐप पर आने वाली अनजान कॉल्स को साइलेंट करने का तरीका बताने जा रहे हैं.

एंड्रॉयड पर यह तरीका करेगा काम - अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले व्हाट्सऐप ऐप को ओपन करें. अब प्राइवेसी में

जाकर कॉल्स पर जाएं. यहां आपको साइलेंस अननॉन कॉलर का ऑप्शन दिखेगा. इसका टॉगल ऑन करते ही अनजान नंबरों से आने वाली सारी व्हाट्सऐप कॉल्स साइलेंट हो जाएंगी.

आईफोन पर ऐसे करें साइलेंट - आईफोन पर भी अनजान कॉल्स का साइलेंट करने का तरीका एंड्रॉयड जैसा ही है. यहां भी प्राइवेसी में जाकर कॉल्स के ऑप्शन पर टैप करें. टैप करने के बाद साइलेंस अननोन कॉलर का ऑप्शन आएगा. इसका टॉगल ऑन कर दें. अनजान नंबरो से आने वाली कॉल्स को साइलेंस करने के कई फायदे होते हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि इससे डिस्ट्रैक्शन कम हो जाती है. अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो ये कॉल्स आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी. साथ ही यह सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर के तौर पर भी काम करती है. इसकी मदद से केवल ऐसे कॉलर ही आपको व्हाट्सऐप कॉल कर पाएंगे, जिनके नंबर आपके पास सेव है या जिनसे आपकी पहले बातचीत हो चुकी है.

कॉल्स का रहेगा पूरा हिसाब - व्हाट्सऐप के इस फीचर की खास बात यह है कि साइलेंस होने के बाद भी कॉल्स का पूरा रिकॉर्ड रहता है. आप कॉल्स टैब में जाकर देख सकते हैं कि आपको किसने कॉल किया है. जरूरी होने पर आप उस नंबर से दोबारा संपर्क कर सकते हैं.

जनरल नॉलेज

आम बजट के साथ कब से पेश किया जा रहा है रेल बजट, जानें पहले क्यों होता था अलग?

1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि आम बजट के साथ कब से पेश किया जा रहा है रेल बजट.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं. यह उनका लगातार नौंवा बजट होगा. उन्होंने अपना पहला बजट 2019 में पेश किया था. भारत के बजट के इतिहास में सबसे जरूरी सुधारों में से एक रेल बजट का केंद्रीय बजट में विलय था. इससे 92 साल से चली आ रही प्रथा खत्म हो गई.

रेल बजट और केंद्रीय बजट - भारत में 2017 से रेल बजट को केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जा रहा है. पहला संयुक्त बजट 1 फरवरी 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया था. उस साल से संसद में दो अलग-अलग वित्तीय बयानों के बजाय 1 फरवरी को सुबह 11:00 बजे सिर्फ एक समेकित बजट भाषण दिया जाता है.

पहले रेल बजट अलग क्यों था - अलग रेल बजट की परंपरा 1924 में ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुई थी. इस फैसले को एक्वर्थ कमेटी की सिफारिश के बाद लिया गया था. उस समय भारतीय रेलवे कुल सरकारी खर्च का लगभग 84% था. इस वजह से इसे सामान्य बजट के तहत प्रबंधित करना काफी बड़ा और मुश्किल था.

औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में रेलवे का दबदबा - आजादी से पहले के दौर में रेलवे भारत की अर्थव्यवस्था और प्रशासन की रीढ़ थी. माल ढुलाई, यात्री यात्रा, सैन्य लॉजिस्टिक्स और राजस्व सभी रेलवे पर काफी ज्यादा निर्भर थे. इस बड़े वित्तीय प्रभाव ने एक अलग रेल बजट को सही ठहराया.

सालों में क्या हुआ बदलाव - आर्थिक विविधीकरण और बाकी क्षेत्र के उदय के साथ कुल बजट में रेलवे का हिस्सा धीरे-धीरे कम होने लगा. 2016 तक भारतीय रेलवे कुल सरकारी खर्च का सिर्फ लगभग 15% ही था. एक अलग से बजट बनाए रखने का अब कोई व्यावहारिक उद्देश्य नहीं रहा.

बजटों को विलय करने का निर्णय - 2016 में नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय की अध्यक्षता वाली एक समिति ने रेल बजट को केंद्रीय बजट के साथ विलय करने की सिफारिश की. सरकार ने सरलीकरण, पारदर्शिता और बेहतर वित्तीय प्रबंधन की जरूरत का हवाला देते हुए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया. इस फैसले से उस परंपरा का औपचारिक रूप से अंत हो गया जो 1924 से चली आ रही थी.

रेल बजट मर्जर के फायदे - इस मर्जर से कई फायदे हुए हैं. इसने बजट बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाया है और वित्त मंत्रालय को संसाधनों को ज्यादा कुशलता से बांटने के लिए अनुमति दी है. भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ी राहत यह थी कि उसे अब केंद्र सरकार को सालाना डिविडेंड का पेमेंट नहीं करना पड़ता था. इससे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, सुरक्षा सुधार और मॉर्डनाइजेशन के लिए फंड उपलब्ध हुआ.

शेख हसीना के दिल्ली में भाषण का असर! बांग्लादेश ने रद्द किया इंडियन इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट

एजेंसी ढाका

बांग्लादेश ने चटगांव के मिरसराय इलाके में प्रस्तावित इंडियन इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट को किया रद्द कर दिया है। यूनुस सरकार ने इसके बजाय उसी जमीन पर एक डेडिकेटेड डिफेंस इंडस्ट्रियल जोन बनाने का ऑप्शन चुना है। यह ऐलान दो दिन पहले बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी (BEZA) और बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी (BIDA) के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन चौधरी आशिक महमूद बिन हारून ने हाल ही में चीफ एडवाइजर मुहम्मद यूनुस की अध्यक्षता में हुई एक हाई-लेवल गवर्निंग बोर्ड मीटिंग के बाद किया। यूनुस सरकार ने यह फैसला नई दिल्ली में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के सार्वजनिक भाषण के बाद किया है। यूनुस सरकार के इस फैसले से भारत-बांग्लादेश संबंधों में तनाव और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। भारत और बांग्लादेश में 2015 में मिरसराय इलाके में इंडियन इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट को लेकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया था। इसके अंतर्गत बांग्लादेश के नेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन फ्रेमवर्क के अंदर मिरसराय में सैकड़ों एकड़ जमीन और बागेरहाट के मोंगला में एक और साइट को विकसित करना था। इसके लिए भारत ने बांग्लादेश को रियायती दरों पर लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया था। इस प्रोजेक्ट का मकसद भारत और बांग्लादेश में इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना था। यूनुस सरकार का दावा है कि बांग्लादेश की तरफ से इंटरनेशनल टेंडर की इजाज़त देने समेत प्रोग्रेस के लिए बार-बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद, कोई खास तरक्की नहीं हुई। बांग्लादेशी अधिकारियों का दावा है कि इस प्रोजेक्ट में दिए गए फंड का सिर्फ लगभग एक परसेंट ही इस्तेमाल हुआ। भारतीय कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत कम दिलचस्पी दिखाई, जिससे प्रोजेक्ट को 2025 के बीच तक G2G फ्रेमवर्क से डीलिस्ट कर दिया गया।

BEZA की चौथी गवर्निंग बोर्ड मीटिंग में लिए गए एक पॉलिसी फैसले में, मिरसराय में पहले से दी गई खाली ज़मीन में से लगभग 850 एकड़ को अब मिलिट्री इकोनॉमिक ज़ोन या डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क के लिए तय किया गया है। इस पहल का मकसद बांग्लादेश की घरेलू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाना है, जिसमें मिलिट्री इक्विपमेंट, कंपोनेंट और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी बनाने पर फोकस किया जाएगा।

डिफेंस इकोनॉमिक ज़ोन में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और संभावित इन्वेस्टर्स के बारे में सवालों के जवाब में, आशिक चौधरी ने कहा कि बांग्लादेश के साथ दोस्ताना संबंध रखने वाले कई देशों के साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि इस समय यह बताना संभव नहीं है कि कौन से मिलिट्री उपकरण बनाए जाएंगे, क्योंकि यह डिमांड के आधार पर तय किया जाएगा। BEZA गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग में कई अन्य मुद्दों को भी पॉलिसी मंजूरी दी गई। मुख्य फैसलों में से एक फ्री ट्रेड ज़ोन स्थापित करना था। इंडियन इकोनॉमिक ज़ोन प्रोजेक्ट को रद्द करने का फैसला ऐसे समय हुआ है, जब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत-बांग्लादेश संबंध बिगड़ रहे हैं। इस घटना का दोनों देशों के आर्थिक संबंधों पर असर पड़ने की संभावना है। बांग्लादेश के कई प्रोजेक्ट्स भारत के इन्वेस्टमेंट और लाइन ऑफ क्रेडिट पर टिके हुए हैं। इंडियन इकोनॉमिक ज़ोन को एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के तौर पर देखा गया था जो दोनों देशों के मज़बूत होते संबंधों का प्रतीक था। इससे बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा होने की उम्मीद थी। लेकिन, अब यूनुस सरकार के फैसले से बांग्लादेशी लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है।

`ग्रीस आग से खेलना बंद करे', भारत के दोस्त को धमका रहे तुर्की के अखबार, एर्दोगन की बौखलाहट देखें

एजेंसी अंकारा

तुर्की की मीडिया का काम बस प्रोपेगेंडा फैलाना है। इसने पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष में भारत के खिलाफ जमकर झूठी खबरें फैलाई थी और अब वो भारत के दोस्त ग्रीस के खिलाफ ऐसा ही कर रहा है। तुर्की की मीडिया में ग्रीस को लेकर आग उगला जा रहा है। तुर्की की मीडिया में ग्रीस को धमकाकर लिखा जा रहा है कि वो 'आग से खेलना बंद करे।' तुर्की की मीडिया एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे लगता है कि ग्रीस, एजियन सागर में बयानबाजी और कानूनी तौर पर तनाव भड़का रहा है। तुर्की की मीडिया में अभी 6 मुद्दों पर जमकर लिखे जा रहे हैं। 1- एजियन सागर में ग्रीक की समुद्री सीमा और शक्ति की विस्तार की कोशिश, 2- तुर्की NAVTEX और 25वीं मेरिडियन, 3- एजियन सागर में ग्रीस का डिफेंस, 4- 2027 तक अंकारा की लंबी अवधि की योजना, 5- तूर्की का यूरोफाइटर टायफून खरीदने के लिए डील और 6- ग्रीस, एजियन सागर में आग से खेल रहा है। तुर्की के अखबार सोझू ने समुद्री सीमा पर ग्रीस के रुख को जानबूझकर तनाव बढ़ाने वाली रणनीति बताया है। अखबार सिर्फ तथ्य नहीं बता रहा, बल्कि सीधे-सीधे टिप्पणी कर रहा है कि एथेंस "आग से खेल रहा है" और इन बयानों को 2026 की एक बड़ी योजना से जोड़ रहा है। रिपोर्ट में ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरापेट्रिटिस की बातों पर खास तौर पर जोर दिया गया है, जिसे सोझू एकतरफा और बिना बातचीत के समझौता न करने वाला बता रहा है।

वो गेरापेट्रिटिस की बातों को ऐसा कहकर हवा दे रहा है कि "एजियन सागर में ग्रीस की समुद्री सीमा को 12 मील तक बढ़ाना ग्रीस का 'अविभाज्य अधिकार' है और ग्रीस इस फैसले के लिए टाइमटेबल खुद तय करेगा।" वहीं, मिलियेट अखबार ने एजियन सागर को लेकर लिखा है कि 'तुर्की एजियन सागर की घेराबंदी कर रहा है।' मिलियेट अखबार, एजियन की स्थिति को तुर्की की सफल रणनीति बताता है, जिसका दायरा 2027 तक फैला हुआ है।

ये अखबार अपनी रिपोर्टस में कहता है कि एजियन सागर में ग्रीस फंसा हुआ है और लगातार दबाव की स्थिति में हैं। वहीं तुर्किये नाम के अखबार ने ग्रीस को यूरोफाइटर टायफून लड़ाकू विमानों को लेकर चेतावनी दी है। उसने तुर्की के यूरोफाइटर टायफून फाइटर जेट डील के बारे में लिखा है। इसमें लिखा गया है कि कैसे तुर्की के फाइटर जेट खरीदने से ग्रीस टेंशन में है। ये अखबार इस फाइटर जेट को हासिल करने की कोशिशों को एक राजनीतिक आश्चर्य की तरफ पेश करता है।

चीन की PL-17 कलिर मिसाइल की पहली बार करीब से झलक, PL-15 से कितनी खतरनाक, 400KM है रेंज

एजेंसी बीजिंग

पहलगाम हमले के बाद, जब ऐसा लगने लगा था कि भारत, पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है, PL-15 एयर-टू-एयर मिसाइल के बारे में बताया था। हमारी रिपोर्ट में सबसे खास बात ये थी कि चीन ने पाकिस्तान को PLA एयरफोर्स के लिए जो PL-15 बनाया गया था, वो पाकिस्तान को सौंपा था। इसकी रेंज 200 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है। जबकि PL-15 के एक्सपोर्ट वैरिएंट की रेंज 150 किलोमीटर के आसपास है। बाद में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पता चला था कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। अब हम आपको PL-17 मिसाइल के बारे में एडवांस जानकारी देने जा रहे हैं। क्या पता, अगले भारत-पाकिस्तान संघर्ष में इस मिसाइल का भी इस्तेमाल हो ही जाए। PL-17 को पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स (PLAAF) का सबसे रहस्यमय हथियार माना जाता है। ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक PL-15 जैसे ही, लेकिन इसकी क्षमता और रेंज काफी ज्यादा है। इस मिसाइल को पहली बार काफी करीब से देखा गया है। हालांकि यह मिसाइल काफी समय से मौजूद है, लेकिन इसके बारे में लगभग कोई भी आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है। इस मिसाइल को लेकर चर्चा इसलिए भी तेज है, क्योंकि अमेरिकी वायुसेना ने इन मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के उत्पादन में तेजी ला दी है। PL-17 की यह तस्वीर असली लगती है, लेकिन हम इस बारे में पक्का नहीं कह सकते। तस्वीर की तारीख और जगह भी साफ नहीं है, लेकिन इसमें एक PL-17 के पूरे साइज का मॉडल दिख रहा है। द वॉर जोन ने लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि इसे चीन में किसी ट्रेडशो या प्रदर्शनी के दौरान डिस्प्ले स्टैंड पर रखा गया था। एक आदमी मिसाइल के सामने पोज देते हुए फोटो खिंचवा रहा है। इस आदमी का चेहरा धुंधला किया हुआ है जबकि हथियार के पीछे J-20 स्टील्थ फाइटर को प्रमोट करने वाला एक बोर्ड लगा है। PL-17 की पहली धुंधली तस्वीर करीब 10 साल पहले सामने आई थी, इसीलिए अभी इस तस्वीर का सामने आना थोड़ा चौंकाने वाला भी है। शुरूआती आकलन में PL-17 को इसकी बहुत बड़ी साइज (करीब 20 फीट) लंबी होने की वजह से बहुत लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल माना गया। शायद इसे एयर टैंकर विमान और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसा लग रहा है कि PL-17 में डुअल-पल्स रॉकेट मोटर है, जबकि कंट्रोल चार छोटे टेल फिन और एक थ्रस्ट-वेक्टरिंग नोजल से मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक, मिसाइल की रेंज करीब 250 मील यानि 400 किलोमीटर के आसपास होने की संभावना है। जबकि इसकी टॉप स्पीड मैक 4 के करीब हो सकती है। हालांकि ये आंकड़े लड़ाई के मैदान और परिस्थितियों के मुताबिक अलग हो सकते हैं। माना जा रहा है कि इसका गाइडेंस दो-तरफा डेटा लिंक और एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे (AESA) सीकर के कॉम्बिनेशन से हासिल किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर के प्रति बहुत ज्यादा प्रतिरोधी बताया जाता है। मुख्य सीकर को सपोर्ट करने के लिए एक पैसिव एंटी-रेडिएशन सीकर की भी खबरें हैं। लेकिन तस्वीर से लगता है कि इसे खास तौर पर एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेटर (GMTI) रडार एयरक्राफ्ट के खिलाफ उपयोगी हो सकता है और फाइटर जेट के खिलाफ ये शायद ही कारगर साबित हो। अब तक PL-17 सिर्फ J-16 पर लगा हुआ देखा गया है, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि इसे J-20 फाइटर जेट में लगाया गया है। लेकिन चूंकी इसे इस विमान के बाहरी हिस्से में इस मिसाइल को लगाया गया है, इसलिए J-20 की स्टील्थ क्षमता एक्सपोज हो जाएगी। इसके अलावा एक बहुत जरूरी जानकारी ये भी मिलती है कि ये मिसाइल काफी लंबी है, इसलिए इसे J-10C फाइटर जेट या J-35 स्टील्थ फाइटर जेट में इंटीग्रेट करना काफी मुश्किल है। इसलिए इस मिसाइल को पाकिस्तान को बेचे जाने की उम्मीद न्यूनतम है। इसके अलावा बहुत ज्यादा मुमकिन है कि चीनी सेना इसे J-36 छठी पीढ़ी के जेट में इंटीग्रेट करने की तैयारी कर रही हो, इससे इस मिसाइल का मैक्सिमम रेंज के साथ इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन इसे किसी और देश को बेचे जाने की संभावना अत्यंत कम लग रहा है। इसीलिए भारत को पाकिस्तान के फ्रंट पर इस मिसाइल के इस्तेमाल की आशंका नहीं के बराबर होगी। हालांकि हम लापरवाह नहीं हो सकते और हमें पहले से तैयार रहने की जरूरत होगी।

पाकिस्तान की इन 4 पनडुब्बियों ने कैसे बढ़ाई भारत की टेंशन, अरब सागर से हिंद महासागर तक खतरा

एजेंसी इस्लामाबाद

पाकिस्तानी नौसेना इन दिनों एक क्षेत्र में भारतीय नौसेना से चार गुना आगे निकल गई है। यह क्षेत्र एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) सिस्टम से लैस पनडुब्बियों की तैनाती का है। पाकिस्तानी नौसेना एआईपी तकनीक से लैस चार पनडुब्बियों का संचालन कर रही है। वहीं, भारतीय नौसेना अभी भी इस सिस्टम से लैस पहली पनडुब्बी को पाने के इंतजार में है। पाकिस्तानी नौसेना की एआईपी सिस्टम से लैस ये पनडुब्बियां तेजी से बदलते हालात के दौरान भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। इन पनडुब्बियों को डिटेक्ट करना भारतीय नौसेना के लिए टेढ़ी खीर हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तक अपनी पनडुब्बियों को आसानी से तैनात कर सकता है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) सिस्टम डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को सतह पर आए बिना या स्नोर्कल का उपयोग किए बिना, हफ्तों तक पानी के नीचे रहने और काम करने में सक्षम बनाता है। यह सिस्टम पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की बैटरी को रिचार्ज करके, उन्हें अधिक शांत और दुश्मन के रडार से छिपने में बेहतर बनाता है। AIP तकनीक के साथ, पनडुब्बियों को हवा लेने के लिए बार-बार सतह पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे उनकी पानी के भीतर रहने की क्षमता बढ़ जाती है। यह पारंपरिक डीजल इंजनों की तुलना में बहुत कम शोर पैदा करती है, जिससे दुश्मन के लिए उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है।

क्रम संख्या	पनडुब्बी का नाम	लॉन्च डेट
1	पीएनएस हैंगोर	26 अप्रैल 2024
2	पीएनएस शुशुक	15 मार्च 2025
3	पीएनएस मैंग्रो	15 अगस्त 2025
4	पीएनएस गाजी	17 दिसंबर 2025

पाकिस्तान वर्तमान में AIP सिस्टम से लैस चार पनडुब्बियों का संचालन कर रहा है। ये सभी पनडुब्बियां चीन में बनी हैं। यह चीन की युआन-श्रेणी (टाइप 039ए परिवार) पनडुब्बी का एक्सपोर्ट वेरिएंट है। पाकिस्तान ने अप्रैल 2015 में चीन से आठ पनडुब्बियों की खरीद स्वीकार की थी। समझौते के अनुसार, चार पनडुब्बियों का निर्माण पाकिस्तान की केएस एंड ईडब्ल्यू फैक्ट्री में किया जाएगा, जबकि अन्य चार का उत्पादन चीन में हो चुका है। शुरुआती योजना के अनुसार 2022 और 2028 के बीच 8 पनडुब्बियां डिलीवरी की जानी थीं, हालांकि अभी तक सिर्फ चार पनडुब्बियों की डिलीवरी हो सकी है। भारतीय नौसेना व्यापक पैमाने पर एंटी सबमरीन वायरफेयर सिस्टम को ऑपरेट करती है। इसमें सोनबॉय, मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्शन सिस्टम, एंटी शिप मिसाइलों से लैस P-8I पोसाइडन विमान, तटीय निगरानी के लिए विशेष सोनार और टॉरपीडो से लैस स्वदेशी रूप से निर्मित कमोर्ता क्लास के एंटी सबमरीन वारफेयर शिप शामिल हैं। इस क्लास के युद्धपोतों में आईएनएस अर्नाला, जल्द लॉन्च होने वाला आईएनएस अंजदीप और हाल में ही लॉन्च किए गए आईएनएस अमिनी और आईएनएस अजय जैसे उथले पानी के पनडुब्बी रोधी प्लेटफार्म शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना के एमएच-60आर सीहॉक हेलीकॉप्टर पनडुब्बी रोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

ईरान बनाम इजरायल, क्या ईरानी हमले से USS अब्राहम लिंकन की तरह खुद को बचा सकते हैं इजरायली युद्धपोत

एजेंसी तेल अवीव

ईरान और अमेरिका युद्ध के कगार पर खड़े हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन ईरान के करीब पहुंच चुका है। इस बीच अमेरिकी नौसेना ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य तैयारियों की जांच की है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है, तो इसमें इजरायल भी शामिल होगा। ऐसे में ईरान पलटवार करते हुए इजरायल को निशाना बना सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान का पहला लक्ष्य इजरायली युद्धपोत होंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या इजरायली युद्धपोत अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन की तरह ईरानी हमले से खुद को बचा सकते हैं। जानकारी के अनुसार, इजरायली नौसेना सा'आर 6 कार्वेट का इस्तेमाल करती है। सा'आर 6 कार्वेट मिसाइल हमलों से बचाव के लिए एडवांस्ड C-डोम और बराक 8 सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमले को नाकाम करने में काफी सक्षम हैं, लेकिन इनमें USS अब्राहम लिंकन जैसे हथियारों की वेराइटी नहीं है। अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर मल्टी-शिप एजिस डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इजरायल ने ऐसे ही डिफेंस सिस्टम को खुद के लिए भी विकसित किया है। USS अब्राहम लिंकन समुद्र में तैरता एयरबेस है। यह तीन विध्वंसक पोतों की निगरानी में अपने मिशन को अंजाम देता है। वहीं, इजरायली नौसेना मुख्य रूप से छोटे और हाई टेक नेवल शिप पर निर्भर है। USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर खतरों का अकेले सामना नहीं करता है, बल्कि इसके साथ एजिस कॉम्बैट सिस्टम से लैस क्रूजर और विध्वंसक जहाजों का बेड़ा होता है। ये जहाज सैकड़ों किलोमीटर की रेंज में डिफेंस शील्ड का निर्माण करते हैं और खतरे को एयरक्राफ्ट कैरियर के पास पहुंचने से पहले ही मार गिराते हैं। इजरायली नौसेना मुख्य रूप से सा'आर 6 युद्धपोत पर निर्भर है। इसका वजन लगभग 1900 टन है। वहीं, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर 100000 टन का होता है। इसके बावजूद इजरायली सा'आर 6 युद्धपोत जर्मनी के शिप सेंसर और हथियारों से लैस हैं। इन्हें खास तौर पर हिजबुल्लाह और ईरानी हमलों से अपने महत्वपूर्ण ऑफशोर गैस रिग्स की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। इजरायली सा'आर 6 युद्धपोत आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के नेवल वर्जन C-डोम से लैस हैं। C-डोम सा'आर 6 युद्धपोत को एक साथ दर्जनों हमलों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा सा'आर 6 युद्धपोत बराक 8 मिसाइल सिस्टम से भी लैस है, जो 70-100 किलोमीटर दूर तक क्रूज मिसाइलों और विमानों को मार गिरा सकता है। बराक-8 बहुत अडवांस डिफेंस सिस्टम है, जो एक साथ कई लक्ष्यों को संभालने में सक्षम है। सा'आर 6 युद्धपोत MF-STAR रडार का उपयोग करता है, जिसकी तुलना अक्सर अमेरिकी नौसेना के SPY-1 एजिस रडार से की जाती है। यह डिजिटल रडार एक साथ सैकड़ों टारगेट को ट्रैक कर सकता है। इनमें समुद्र की सतह पर उड़ने वाली मिसाइलों से लेकर उच्च ऊंचाई तक उड़ान भरने वाले विमान शामिल हैं। यह अपने गोला-बारूद को बेहद सटीकता के साथ दुश्मन पर निशाना भी लगा सकता है। जिससे इसके हमले काफी प्रभावशाली होते हैं।

टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान ने भरी हुंकार, ऑस्ट्रेलिया को रौंदकर दिखाया दम; बाबर आजम हुए फ्लॉप

नई दिल्ली, एजेंसी | टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. पहला टी20 गुरुवार (29 जनवरी) को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया. मुकाबले में पाकिस्तान ने 22 रन से जीत दर्ज करते हुए ऑस्ट्रेलिया को रौंदा. आगामी टी20 विश्व कप से पहले यह जीत पाकिस्तान के लिए बड़ा बूस्ट होगा.

हालांकि गौर करने वाली बात यह रही कि पाकिस्तान ने मुकाबला तो जीत लिया, लेकिन टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम फ्लॉप नजर आए. बाबर का फ्लॉप होना टी20 टूर्नामेंट से पहले मेन इन ग्रीन के लिए बड़ी मुश्किल हो सकता है. मुकाबले में बाबर 20 गेंदों में सिर्फ 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इस दौरान उनके बल्ले से 1 चौका और 1 छक्का निकला.

टॉस जीतकर पाकिस्तान का सही फैसला

बता दें कि मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम का यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ. पहले बैटिंग के लिए उतरी मेजबान टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 168 रन बोर्ड पर लगाए.

हालांकि ऑस्ट्रेलिया को देखते हुए यह कोई बड़ा टोटल नहीं था, लेकिन पाक गेंदबाजों ने कमाल करते हुए टीम को जीत दिलाई. बताते चलें कि पाकिस्तान के लिए ओपनिंग पर उतरे सैम अयूब ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 22 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 40 रन बनाए. इसके अलावा कोई भी दूसरा बल्लेबाज 40 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका. चार बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके.

रन चेज में ऑस्ट्रेलिया फ्लॉप

फिर रन चेज के लिए मैदान पर उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर सिर्फ 146 रन तक ही पहुंच सकी. टीम की शुरुआत काफी खराब रही. कंगारुओं ने सिर्फ 28 रन के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद टीम खुद को संभाल नहीं पाई. टीम के लिए नंबर तीन पर उतरे कैमरून ग्रीन ने सबसे बड़ी पारी खेली. उन्होंने 31 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 36 रन स्कोर किए. इस दौरान पाकिस्तान के लिए अबरार अहमद और सैम अयूब ने सबसे ज्यादा 2-2 विकेट लिए.

बेंगलुरु ने छठी जीत के साथ डायरेक्ट फाइनल में बनाई जगह, हैरिस-मंधाना चमकी; यूपी वॉरियर्स पर लटकी तलवार

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला जीतकर डायरेक्ट WPL 2026 के फाइनल में जगह बना ली है.

नई दिल्ली, एजेंसी | महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) का 18वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स के बीच वडोदरा में खेला गया. मुकाबले में आरसीबी ने 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. इस जीत के साथ टीम ने डायरेक्ट फाइनल में जगह बना ली है. वहीं यूपी वॉरियर्स का बुरा हाल हुआ है. आरसीबी ने पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहकर अपने लीग स्टेज के मैच समाप्त किए. मुकाबले में बेंगलुरु को जीत दिलाने में ग्रेस हैरिस और स्मृति मंधाना ने अहम योगदान दिया.

अब यूपी को अपना आखिरी लीग मैच 01 फरवरी को दिल्ली के खिलाफ खेलना है. प्लेऑफ में जगह हासिल करने के लिए टीम को इस मैच में जीत हासिल करने के साथ-साथ बाकी टीमों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा.

मैच का हाल - मुकाबले में पहले बैटिंग के लिए उतरी यूपी की टीम ने 20 ओवर में 143/8 रन बोर्ड पर लगाए. टीम के लिए दीप्ति शर्मा ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 43 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 55 रन स्कोर किए. इसके अलावा मेग लेनिंग ने 41 रनों की पारी खेली. टीम की 6 बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकीं, जिसमें तीन बल्लेबाज बिना खाता खोले ही रहीं. वहीं इस दौरान आरसीबी के लिए नादिन डी क्लर्क ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए.

इस साल बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद, नयी पिस्टल संतुलन के मामले में बेहतर है: मनु भाकर

नयी दिल्ली, एजेंसी | दो बार की ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर ने बृहस्पतिवार को इटली की हथियार निर्माता कंपनी पार्डिनी की नयी स्पोर्ट्स पिस्टल संतुलन के लिहाज से बेहतर करार देते हुए उम्मीद जताई कि बीते साल उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने के बाद वह इस साल ज्यादा पोडियम (शीर्ष तीन में जगह) हासिल कर पाएंगी।

यह साल भारतीय निशानेबाजों का अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर बेहद व्यस्त रहने वाला है। 2026 में भारतीय निशानेबाजों के लिए मुख्य कार्यक्रमों में घरेलू महाद्वीपीय चैम्पियनशिप, एशियाई खेल और कई आईएसएसएफ विश्व कप चरण शामिल हैं। इसमें पहली बड़ी प्रतियोगिता एशियाई चैम्पियनशिप दो से 14 फरवरी तक नयी दिल्ली के डॉ. करणी सिंह रेंज में आयोजित होगी। इसमें 17 देशों के 300 से अधिक निशानेबाज हिस्सा लेंगे।

इस 23 साल की निशानेबाज ने कहा, '' 2025 मेरे लिए एक तरह से पूरा चक्र रहा। कुछ मुकाबलों में मेरा प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और मैं अच्छी फॉर्म में थी लेकिन इस दौरान पोडियम स्थान अपेक्षाकृत कम रहे। उम्मीद है कि इसमें बदलाव होगा और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगी।"

मनु 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल स्पर्धा में नयी पिस्टल का इस्तेमाल करेंगी, लेकिन 10 मीटर एयर पिस्टल में वह उसी पिस्टल से निशानेबाजी जारी रखेंगी, जिससे वह 2017 से खेलती आ रही हैं।

नहीं रहे दिग्गज कोच माइकल नोब्स, ऑस्ट्रेलिया से था गहरा ताल्लुक; जानें कैसे हुई मौत

भारत के पूर्व हॉकी कोच माइकल नोब्स का 72 साल की उम्र में निधन हो गया. तो आइए जानते हैं कि कैसे उनकी मृत्यु हुई.

नई दिल्ली, एजेंसी | भारतीय हॉकी के पूर्व कोच माइकल नोब्स का निधन हो गया. उन्होंने 72 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा. बता दें कि भारत को कोचिंग देने वाले नोब्स एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे. उन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत के लिए कोच का किरदार अदा किया था. माइकल नोब्स एक भरोसेमंद डिफेंडर थे. वह उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा थे, जब कंगारुओं को हॉकी में सबसे मजबूत देशों में से एक गिना जाता था.

बता दें कि नोब्स ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 1979 से 1985 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला. इस दौरान उन्होंने 76 मुकाबले खेले. अपने करियर के दौरान उन्होंने बॉम्बे में हुए 1981 के हॉकी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया था. इसके अलावा वह 1984 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में भी कंगारू टीम का हिस्सा थे.

कैसे हुई मृत्यु? - एक सवाल यह भी उठ रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज और पूर्व भारतीय कोच की मृत्यु कैसे हुई? तो आपको बता दें कि वह लंबे वक्त से बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके चलते उनका निधन हो गया. नोब्स का दुनिया से चले जाना ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और भारत के लिए बल्कि पूरे खेल जगत के लिए बड़ी क्षति है.

हॉकी ऑस्ट्रेलिया ने जताया दुख - दिग्गज के निधन पर हॉकी ऑस्ट्रेलिया ने दुख जताते हुए एक पोस्ट में लिखा, 'हॉकी ऑस्ट्रेलिया ने ओलंपियन, प्रतिष्ठित कोच और ऑस्ट्रेलियाई हॉकी के सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक, माइकल नॉब्स (कूकाबुरा #252) को श्रद्धांजलि दी है, जिनका निधन हो गया है.'

इंटरनेशनल हॉकी फेडरनेशन का भी आया रिएक्शन - इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से एक्स पर पोस्ट करते हुए एफआईएच अध्यक्ष तैयब इकराम के हवाले से लिखा गया, 'ऑस्ट्रेलियाई हॉकी नेशनल टीम के पूर्व ओलंपियन और कोच माइकल नॉब्स के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. 1981 एफआईएच हॉकी विश्व कप में कांस्य पदक सहित अपने शानदार खेल करियर के बाद, माइकल नॉब्स ने ऑस्ट्रेलिया और इंटरनेशनल लेवल पर, जापान और अन्य देशों में भी सफल कोचिंग करियर की शुरुआत की.'

टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप

नई दिल्ली, एजेंसी | टी20 विश्व कप 2026 से ठीक पहले अमेरिकी क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार बल्लेबाज आरोन जोन्स को आईसीसी ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. उन पर मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद यह कड़ा कदम उठाया गया है.

आईसीसी ने बुधवार को आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि आरोन जोन्स को सभी तरह की क्रिकेट गतिविधियों से अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है. जोन्स पर कुल पांच आरोप लगाए गए हैं, जो आईसीसी और क्रिकेट वेस्टइंडीज के एंटी-करप्शन कोड के उल्लंघन से जुड़े हैं. उन्हें इन आरोपों का जवाब देने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है.

किन मामलों में लगे हैं आरोप - आरोन जोन्स पर लगे पांच आरोपों में से तीन आरोप 2023-24 में खेले गए बारबाडोस आधारित बीआईएम10 टी20 टूर्नामेंट से जुड़े हैं. वहीं, बाकी दो आरोप उनके अंतरराष्ट्रीय मैचों से संबंधित बताए जा रहे हैं. आईसीसी के मुताबिक, इनमें से एक गंभीर आरोप यह है कि जोन्स ने मैच के नतीजे, या किसी अन्य पहलू को गलत तरीके से प्रभावित करने या ऐसा करने की साजिश में शामिल होने की कोशिश की.

आईसीसी ने अपने बयान में यह भी साफ किया है कि यह जांच अभी जारी है और आने वाले समय में अन्य खिलाड़ियों या इससे जुड़े लोगों पर भी आरोप लग सकते हैं. हालांकि, जांच पूरी होने तक आईसीसी इस मामले पर और कोई टिप्पणी नहीं करेगा.

अमेरिका के लिए अहम खिलाड़ी रहे हैं जोन्स - 31 वर्षीय आरोन जोन्स अमेरिका के लिए बेहद अहम खिलाड़ी माने जाते रहे हैं. उन्होंने 2019 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था.

व्यापार

अब मिडिल क्लास वाले भी खरीद पाएंगे बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज! इंडिया-ईयू ट्रेड डील से सस्ती होंगी कारें

India-EU Trade Deal के बाद BMW, Mercedes और Audi जैसी लग्जरी कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी 110% से घटकर 10% हो सकती है. आइए जानते हैं कि ऑटो सेक्टर पर इसका कितना असर होगा.

नई दिल्ली, एजेंसी | भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 18 साल से जिस बड़े ट्रेड एग्रीमेंट का इंतजार था, वह अब पूरा हो गया है. 16वें भारत-EU समिट में दोनों पक्षों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA का ऐलान किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह समझौता साल 2027 से लागू हो सकता है. इस डील का सबसे बड़ा फायदा उन भारतीय ग्राहकों को मिलने वाला है, जो BMW, Mercedes और Audi जैसी लग्जरी कार खरीदने का सपना देखते हैं. अब तक भारी इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से ये कारें आम लोगों की पहुंच से बाहर थीं, लेकिन यह डील हालात बदल सकती है.

110% से घटकर 10% होगी इंपोर्ट ड्यूटी

India-EU Trade Deal के तहत यूरोप से भारत आने वाली कारों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी में बड़ी कटौती की गई है. अभी पूरी तरह इंपोर्ट की जाने वाली लग्जरी कारों पर 70% से 110% तक टैक्स लगता है, जिससे उनकी कीमत दोगुनी या उससे भी ज्यादा हो जाती है. नए समझौते के बाद यह ड्यूटी घटकर सिर्फ 10% रह सकती है. इसका सीधा मतलब है कि BMW और Mercedes जैसी कारों की कीमत 50 से 70 प्रतिशत तक कम हो सकती है. उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कार की इंपोर्ट वैल्यू 20 लाख रुपये है, तो पहले उसकी कीमत टैक्स के बाद 45–50 लाख तक पहुंच जाती थी, लेकिन अब वही कार करीब 22–25 लाख रुपये में मिल सकती है.

किन कार ब्रांड्स को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा ?

इस डील का सबसे ज्यादा फायदा BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen और Porsche जैसे यूरोपीय ब्रांड्स को मिलेगा. BMW 3 Series, Mercedes C-Class, Audi A4 और Volkswagen Tiguan जैसी कारें अब ज्यादा लोगों की पहुंच में आ सकती हैं. इससे भारतीय लग्जरी कार बाजार पूरी तरह बदल सकता है.

EV और ऑटो इंडस्ट्री पर क्या होगा असर ?

शुरुआती सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर यह ड्यूटी कट सीमित रह सकती है, ताकि Tata और Mahindra जैसी भारतीय कंपनियों को नुकसान न हो. आगे चलकर यूरोपीय EV ब्रांड्स की एंट्री भी आसान हो सकती है. India-EU Trade Deal मिडिल क्लास ग्राहकों के लिए बड़ी राहत बनकर आ सकता है. अगर ड्यूटी सच में 10% तक घटती है, तो लग्जरी कार खरीदना अब सिर्फ सपना नहीं रहेगा.

लुट गया इंडोनेशिया का ये अमीर शख्स, एक झटके में गंवाए 8,27,59,50,00,000 रुपये

इस अमीर कारोबारी के फैमिली ऑफिस ने बयान जारी कर कहा है कि वे एमएससीआई की रिपोर्ट और टिप्पणियों की समीक्षा कर रहे हैं और सभी संबंधित पक्षों के साथ लगातार बातचीत बनाए रखेंगे.

नई दिल्ली, एजेंसी | इंडोनेशिया के एक बड़े और अमीर कारोबारी को जोरदार झटका लगा है. दरअसल, वैश्विक सूचकांक प्रदाता एमएससीआई (MSCI) ने कुछ इंडोनेशियाई कंपनियों के वैल्यूएशन और शेयरधारक संरचना को लेकर चिंता जताई थी. इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद इंडोनेशियाई शेयर बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली. इसके चलते एक ही दिन में देश के अमीरों की संपत्तियों के वैल्यूएशन में करीब 22 बिलियन डॉलर की गिरावट दर्ज की गई.

हालांकि, सबसे ज्यादा नुकसान इंडोनेशिया के सबसे अमीर व्यक्ति प्रजोगो पंगेस्टु (Prajogo Pangestu) को उठाना पड़ा. ऊर्जा और खनन क्षेत्र में सक्रिय उनकी कंपनियों के शेयरों और कुल पूंजीकरण में करीब 9 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 8.27 लाख करोड़ रुपये की भारी गिरावट आई.

अमीर शख्स को बड़ा झटका - ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, प्रजोगो पंगेस्टु की कुल संपत्ति अब घटकर 31 बिलियन डॉलर रह गई है. सिर्फ इसी साल उनकी संपत्ति में करीब 15 बिलियन डॉलर की कमी आ चुकी है. प्रजोगो की एनर्जी कंपनी बैरिटो पैसिफिक) में 71 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि कोयला और सोने के कारोबार से जुड़ी कंपनी पेट्रिंडो जया क्रियासी में उनकी हिस्सेदारी 84 प्रतिशत है. एक ही दिन में इन दोनों कंपनियों के शेयरों में करीब 12 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई.

इस अमीर कारोबारी के फैमिली ऑफिस ने बयान जारी कर कहा है कि वे एमएससीआई की रिपोर्ट और टिप्पणियों की समीक्षा कर रहे हैं और सभी संबंधित पक्षों के साथ लगातार बातचीत बनाए रखेंगे.

क्यों हुई भारी बिकवाली - बाजार में यह तेज प्रतिक्रिया एमएससीआई की उस रिपोर्ट के बाद देखने को मिली, जिसमें इंडोनेशिया के शेयरधारक रिपोर्टिंग नियमों पर सवाल उठाए गए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, निवेशकों का मानना है कि मौजूदा नियमों के कारण कंपनियों की स्वामित्व संरचना स्पष्ट नहीं रहती, जिससे अनुचित ट्रेडिंग का जोखिम बढ़ सकता है.

एमएससीआई ने उन कंपनियों को लेकर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं की ओर भी इशारा किया है, जहां शेयरों पर नियंत्रण कुछ गिने-चुने लोगों या किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है. इस तरह का अत्यधिक केंद्रीकृत स्वामित्व इंडोनेशिया और एशिया के अन्य हिस्सों में कुछ सबसे बड़ी व्यक्तिगत संपत्तियों के निर्माण का आधार रहा है.

निर्मला सीतारमण बोलीं भारत के व्यापक आर्थिक आधार मजबूत, वैश्विक चुनौतियों पर भी दिया जबाव

वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे व्यापक आर्थिक आधार पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं. वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारत को उच्च विकास पथ पर बनाए रखा गया है.

नई दिल्ली, एजेंसी | केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि भारत का व्यापक आर्थिक आधार अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है. उन्होंने कहा कि देश ने वैश्विक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है, जिसके चलते भारत की संभावित जीडीपी वृद्धि दर बढ़कर सात प्रतिशत तक पहुंच गई है.

वित्त मंत्री ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2025-26 पेश करने के बाद सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा कि भू-राजनीतिक विखंडन और आर्थिक उथल-पुथल से भरी दुनिया में भारत एक वैश्विक चमकते सितारे के रूप में उभर कर सामने आया है जो मजबूत, स्थिर और लगातार आगे बढ़ने वाला है.

पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभर रहा भारत

वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे व्यापक आर्थिक आधार पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं. वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारत को उच्च विकास पथ पर बनाए रखा गया है. हमने अपनी संभावित जीडीपी वृद्धि दर को सुधारकर सात प्रतिशत तक पहुंचाया है. आर्थिक समीक्षा के अनुसार, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत रफ्तार बनाए रखी है. समीक्षा में अगले वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत से 7.2 प्रतिशत के दायरे में रहने का अनुमान जताया गया है.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के अनुमानों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.4 प्रतिशत की दर से बढ़ी है. भारत लगातार चौथे वर्ष दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है. समीक्षा में देश के संभावित वृद्धि अनुमान को तीन वर्ष पहले के 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर अब सात प्रतिशत कर दिया गया है.

100 अरब डॉलर तक एक्सपोर्ट

आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि मूल्य के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश अगले चार वर्षों में कृषि, समुद्री तथा खाद्य एवं पेय पदार्थों के निर्यात को 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा सकता है.

साथ ही, इसमें चेतावनी दी गई है कि बार-बार किए जाने वाले नीतिगत बदलाव आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधा पैदा कर सकते हैं, अनिश्चितता बढ़ा सकते हैं और विदेशी खरीदारों को वैकल्पिक स्रोतों की ओर रुख करने के लिए मजबूर कर सकते हैं. ऐसी स्थिति में खोए हुए निर्यात बाजारों को दोबारा हासिल करना कठिन हो जाएगा.

'वध 2' का ट्रेलर रिलीज़ कहानी में दिखे नीना गुप्ता और संजय मिश्रा

वध 2 का ट्रेलर दर्शकों को एक गहरी, रहस्यमयी और भावनात्मक कहानी की झलक देता है, जिसमें संजय मिश्रा और नीना गुप्ता अपनी प्रभावशाली अदाकारी से फिल्म की आत्मा बनकर उभरते हैं। जेल की पृष्ठभूमि पर आधारित यह थ्रिलर-मिस्ट्री नैतिक उलझनों और सस्पेंस से भरी है। लव फिल्म्स की आगामी थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म वध 2 का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। फिल्म में संजय मिश्रा और नीना गुप्ता मुख्य भूमिका में हैं, इनके साथ शिल्पा शुक्ला, योगिता बिहानी, अक्षय डोगरा, कुमुद मिश्रा भी इस हटके कहानी में नजर आ रहे हैं। 2 मिनट 25 सेकेंड के ट्रेलर में कहानी रहस्यमयी नजर आ रही है, जिससे दर्शकों में उत्सुकता पैदा हो गई है। लव फिल्म्स के लव रंजन और अंकुर गर्ग इस फिल्म के निर्माता हैं। वध 2 का ट्रेलर दर्शकों को एक गंभीर कहानी का अनुभव कराता है। एक्टर संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की परफॉर्मेंस शानदार नजर आ रही है, जो फिल्म की भावनात्मक गहराई को और मजबूत बनाती है। ट्रेलर में कहानी का रहस्य स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहा है, इसलिए दर्शकों के मन में अलग तरह की उत्सुकता पैदा हो गई है। फिल्म जेल और उसके अंदर के कैदियों और पुलिस के बीच गूँथी गई है। 2 मिनट 25 सेकेंड के ट्रेलर से यह पता चल रहा है कि कुमुद मिश्रा, संजय मिश्रा, नए एक्टर अमित के सिंह और शिल्पा शुक्ला जेल की पुलिस के रोल में हैं। नीना गुप्ता एक महिला कैदी हैं, और योगिता बिहानी भी। अक्षय डोगरा का किरदार स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है। इस फिल्म के प्रमोशन की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें संजय मिश्रा और नीना गुप्ता बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं।

मंगलवार को भी बॉर्डर 2 की रही धूम

वॉर ड्रामा सीक्वल, बॉर्डर 2 , बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। सनी देओल स्टारर इस फिल्म ने दर्शकों को दीवाना बना दिया है, जिससे सिनेमाघरों में भारी भीड़ उमड़ रही है और ज़बरदस्त कमाई हो रही है। फिल्म ने रिलीज़ के सिर्फ चार दिनों में ?180 करोड़ कमाए। आइए जानते हैं कि बॉर्डर 2 क्तश्चह्म्स्रद्गह्म् 2ने अपने 5वें दिन, मंगलवार को कितनी कमाई की? बॉर्डर 2 ने अपने 5वें दिन कितनी कमाई की? 23 जनवरी को रिलीज़ हुई बॉर्डर 2 को क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, जिन्होंने इसकी कहानी, युद्ध के दृश्यों और कास्ट की दमदार एक्टिंग की तारीफ की है। यही वजह है कि फिल्म सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है और सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। इसे रिलीज़ के पहले दिन से ही दर्शकों का प्यार मिल रहा है, और यह प्यार हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ रहा है, साथ ही इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बढ़ रहा है। इन सबके बीच, बॉर्डर 2ने पहले दिन 30 करोड़ से शुरुआत की। दूसरे दिन, इसने ?36.5 करोड़ कमाए, जो 21.67 प्रतिशत की बढ़ोतरी थी। तीसरे दिन, फिल्म के कलेक्शन में 49.32 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, और इसने ?54.5 करोड़ कमाए। चौथे दिन, बॉर्डर 2 ने 59 करोड़ कमाए, जो 8.26 प्रतिशत की बढ़ोतरी थी। बॉर्डर 2 ने अपने 5वें दिन, मंगलवार को ?19.50 करोड़ कमाए। इसके साथ ही, 5 दिनों में बॉर्डर 2 का कुल कलेक्शन अब 196.50 करोड़ हो गया है। बॉर्डर 2 अपने 5वें दिन ध्रुव का रिकॉर्ड तोड़ने में नाकाम रही।

बॉलीवुड में नई खटपट
ओरी और सारा के बीच बढ़ा विवाद

सारा पर ओरी का लेटेस्ट कटाक्ष बात तब और बढ़ गई जब ओरी ने ब्रा डिज़ाइन वाला मेश टॉप पहने एक और रील शेयर किया। कमेंट्स में, एक यूज़र ने मज़ाक में पूछा कि ब्रा ने क्या बांध रखा है। ओरी ने जवाब दिया, सारा अली खान के हिट गाने। जब किसी और ने कहा कि सारा शायद इस पर हंस रही होंगी, तो ओरी ने कहा, अपने करियर पर? ज़रूर हंस रही होंगी। यह कमेंट तुरंत वायरल हो गया और इस पर ज़बरदस्त रिएक्शन हुआ। कई यूज़र्स ने ओरी पर सारा के करियर का मज़ाक उड़ाने और पर्सनल बाउंड्री पार करने का आरोप लगाया।

बॉलीवुड में, जहाँ हर कोई किसी न किसी चीज़ के लिए जाना जाता है, वहीं ओरहान अवत्रामणि, जिन्हें लोग ओरी के नाम से जानते हैं, लगभग किसी खास चीज़ के लिए नहीं जाने जाते। वह कोई एक्टर, सिंगर या प्रोड्यूसर नहीं हैं, फिर भी उन्हें हर-लिस्ट सेलिब्रिटी के साथ देखा जाता है। स्टार किड्स से लेकर टॉप एक्टर्स तक, ओरी हर जगह दिखाई देते हैं, जिससे उन्हें बॉलीवुड के सबसे रहस्यमयी सोशल फिगर का टैग मिला है। उनकी रहस्यमयी पर्सनैलिटी, आकर्षक फैशन और बेबाक ऑनलाइन व्यवहार उन्हें लगातार सुर्खियों में बनाए रखते हैं। लेकिन अब, ओरी गलत वजहों से ट्रेंड कर रहे हैं। सारा अली खान के साथ अनबन ओरी कभी सारा अली खान के करीबी दोस्त थे। वे एक दोस्ताना रिश्ता शेयर करने के लिए जाने जाते थे, अक्सर पार्टियों और इवेंट्स में एक साथ देखे जाते थे। सोशल मीडिया पोस्ट की एक सीरीज़ से एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी शुरू होने के बाद अब वह इमेज पूरी तरह से बदल गई है। सारा पर ओरी का लेटेस्ट कटाक्ष बात तब और बढ़ गई जब ओरी ने ब्रा डिज़ाइन वाला मेश टॉप पहने एक और रील शेयर किया। कमेंट्स में, एक यूज़र ने मज़ाक में पूछा कि ब्रा ने क्या बांध रखा है। ओरी ने जवाब दिया, सारा अली खान के हिट गाने। जब किसी और ने कहा कि सारा शायद इस पर हंस रही होंगी, तो ओरी ने कहा, अपने करियर पर? ज़रूर हंस रही होंगी। यह कमेंट तुरंत वायरल हो गया और इस पर ज़बरदस्त रिएक्शन हुआ। कई यूज़र्स ने ओरी पर सारा के करियर का मज़ाक उड़ाने और पर्सनल बाउंड्री पार करने का आरोप लगाया।

कैसे शुरू हुआ विवाद मुसीबत का पहला संकेत तब दिखा जब ओरी ने 3 सबसे बुरे नाम टाइटल वाली एक रील पोस्ट की। वीडियो में सारा, अमृता, और पालक नाम बिना सरनेम के लिस्ट किए गए थे। कई देखने वालों को लगा कि यह सारा अली खान, उनकी मां अमृता सिंह और एक्ट्रेस पलक तिवारी का साफ इशारा था। बाद में रील डिलीट कर दी गई, लेकिन नुकसान हो चुका था। इसके तुरंत बाद, सारा अली खान और उनके भाई इब्राहिम अली खान ने इंस्टाग्राम पर ओरी को अनफॉलो कर दिया, जिससे यह कन्फर्म हो गया कि कुछ बहुत गलत था। सारा का शांत जवाब सारा ने सीधे जवाब न देने का फैसला किया। इसके बजाय, उन्होंने नाम चले गाने के साथ एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की, जिसमें आज़ादी से जीने और फालतू के विवादों से दूर रहने के बारे में लिरिक्स थे। फैंस ने इसे एक हल्का लेकिन क्लासी जवाब माना। अभी तक, ओरी की तरफ से कोई माफी या सफाई नहीं आई है। सारा का अनफॉलो करना, पब्लिक में आलोचना करना और चुप्पी से लगता है कि यह दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। जो बात एक अजीब मज़ाक के तौर पर शुरू हुई थी, वह बॉलीवुड के सबसे चर्चित झगड़ों में से एक बन गई है।

सलमान से विवाद ने छीने अरिजीत सिंह के कई गाने, अब उन्हीं के लिए आखिरी गाना गाकर लिया रिटायरमेंट

संगीत जगत के मौजूदा दिग्गज अरिजीत सिंह ने अचानकर प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेकर हर किसी को हैरान कर दिया है। यहां जानते हैं उनके शिखर से संन्यास तक के सफर के बारे में। साथ ही उनसे जुड़े कुछ किस्सेज

गायकी की दुनिया में प्यार का पर्याय बन चुके सिंगर अरिजीत सिंह ने आज अपने सभी फैंस को अपने एक फैसले से हैरान कर दिया। अरिजीत ने आज अचानक प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा कह दिया। उन्होंने इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दी। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि वो संगीत बनाना जारी रखेंगे, बस प्लेबैक सिंगर के तौर पर अब कोई नया काम नहीं लेंगे। अरिजीत के इस फैसले से उनके फैंस स्तब्ध हैं, तो वहीं हर संगीत प्रेमी पूरी तरह से हैरान है। इस मौके पर जानते हैं अरिजीत से जुड़े कुछ किस्से और कैसे हुई अरिजीत की संगीत में शुरुआतज

सिंगिंग रियलिटी शो से की शुरुआत

25 अप्रैल 1987 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जन्मे अरिजीत सिंह अभी सिर्फ 38 साल के हैं। 38 साल की उम्र में ही अरिजीत ने संगीत जगत की उन बुलंदियों को छुआ है, जिन तक कई कलाकार अपने पूरे करियर में पहुंचने की कोशिश करते रहते हैं। अरिजीत ने संगीत की दुनिया में अपनी शुरुआत साल 2005 में आए रियलिटी शो %फेम गुरुकुल% से की थी। अरिजीत शो में बतौर कंटेस्टेंट नजर आए थे। हालांकि, वो शो जीत नहीं पाए थे। %फेम गुरुकुल% में हार के बाद अरिजीत ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने रियलिटी शो %10 के 10 ले गए दिल% में हिस्सा लिया, जहां उनका मुकाबला फेम गुरुकुल और इंडियन आइडल के विनर्स से था। अरिजीत ने यह शो जीता और 10 लाख रुपये की प्राइज मनी से मुंबई में अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया। इस जीत ने उन्हें म्यूजिक प्रोड्यूसर और सिंगर के रूप में नई शुरुआत दी।

'फिर मोहब्बत' से बॉलीवुड में डेब्यू

अरिजीत का बॉलीवुड डेब्यू 2011 में 'मर्डर 2' फिल्म के गाने 'फिर मोहब्बत' से हुआ, जिसे मिथुन ने कंपोज किया था। यह गाना 2009 में रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन 2011 में रिलीज हुआ। इस गाने ने अरिजीत को पहचान दिलाई और म्यूजिक डायरेक्टर्स की नजर में लाया। यह गाना उनकी मेहनत और धैर्य का नतीजा था, क्योंकि उस समय वे प्रीतम जैसे डायरेक्टर्स के साथ असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे।

'तुम ही हो' गाने ने बदली किस्मत

2013 में आशिकी 2 का गाना 'तुम ही हो' अरिजीत सिंह के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस गाने को म्यूजिक डायरेक्टर मिथुन ने कंपोज किया था और प्रीतम की सलाह पर अरिजीत को यह गाना मिला। यह गाना पहले किसी बड़े सिंगर के लिए विचार किया जा रहा था। जैसा कि उस समय बड़े प्रोजेक्ट्स में आम था। लेकिन अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज में इस गाने को अमर बना दिया। ये गाना आज भी रोमांटिक गानों की लिस्ट में टॉप पर रहता है। इस गाने ने अरिजीत सिंह को रातोंरात स्टार बना दिया। इसके लिए उन्हें अपने करियर का पहला फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला।

सलमान खान के साथ 2014 का विवाद

2014 में एक अवॉर्ड शो में अरिजीत सिंह और सलमान खान के बीच हुई तल्खी ने सुर्खियां बटोरीं थीं। अरिजीत 'आशिकी 2' के गाने 'तुम ही हो' के लिए अवॉर्ड लेने स्टेज पर पहुंचे। इस दौरान वह कैजुअल कपड़ों और चप्पल में देर से आए। सलमान शो होस्ट कर रहे थे और उन्होंने मजाक में पूछा, %सो गए थे क्या?% अरिजीत ने जवाब दिया, %आप लोगों ने सुला दिया।% इस टिप्पणी को सलमान ने अपनी होस्टिंग पर तंज माना। इसके बाद सलमान ने कथित तौर पर अरिजीत को अपनी फिल्मों में गाने से रोक दिया था।

'सुल्तान' के गाने का रिजेक्शन

सलमान खान के साथ विवाद का असर अरिजीत के करियर पर पड़ा। 2016 में सलमान खान की फिल्म 'सुल्तान' के लिए अरिजीत ने 'जग घूमेया' गाना रिकॉर्ड किया था। लेकिन नाराजगी की वजह से सलमान ने इसे हटवाकर राहत फतेह अली खान से गवाया।

गणतंत्र दिवस पर शिक्षक मधुसूदन पटैल हुए सम्मानित

• साधना एक्सप्रेस, गाडरवारा

गाडरवारा*। (रिपोर्टर राजेश नीरस) गत दिवस पर नगर के रूद्र मैदान मे आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह मे ग्राम सांगई की एकीकृत शासकीय नवीन माध्यमिक शाला मे पदस्थ माध्यमिक शिक्षक मधुसूदन पटैल को उत्कृष्ट कार्यो के लिए नपा अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा, एसडीएम कलावती ब्यारे एवं एसडीओपी ललित डागुर ने प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। यहाँ उल्लेखनीय है कि श्री पटैल गत वर्ष भी गणतंत्र दिवस पर सम्मानित हुए थे। इसके अलावा श्री पटैल शिक्षाविद गिजु भाई सम्मान सहित पूर्व मे स्वतंत्रता दिवस पर जिला मुख्यालय पर तत्कालीन कलेक्टर सुश्री ऋजू बाफना से भी सम्मानित हो चुके है। उनके सम्मानित होने पर शिक्षक साथियों ने प्रसन्नता जताई है।

श्रीमती प्रियंका अग्रवाल को मिला जिला स्तरीय सम्मान

• साधना एक्सप्रेस, गाडरवारा

गाडरवारा । (राजेश नीरस) गणतंत्र दिवस के अवसर पर शासकीय सांदीपनि उत्कृष्ट विद्यालय साईंखेड़ा की शिक्षिका श्रीमती प्रियंका अग्रवाल को जिला नरसिंहपुर में शिक्षा विभाग की ओर से अकादमी नवाचार व उत्कृष्ट शिक्षण कार्य के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह व जिलाधीश श्रीमती रजनी सिंह द्वारा जिला

स्तरीय सम्मान 2026 प्रदान किया गया। श्रीमती प्रियंका अग्रवाल इस वर्ष राज्य स्तरीय शैक्षिक संगोष्ठी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाकर 5 सितंबर 2025 को महामहिम राज्यपाल द्वारा सम्मानित हो चुकी है आपकी शिक्षा के प्रति इस लगनशीलता के लिए प्राप्त इस सम्मान पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रतुल इंदुरख्या , विकासखंड शिक्षा अधिकारी सुश्री सीमा डोंगरे , प्राचार्य चंद्रकांत विश्वकर्मा द्वारा बधाईयां प्रेषित करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की गई।

दक्ष इंटरनेशनल स्कूल ने शहीद आशीष शर्मा की जीवन यात्रा का भव्य प्रदर्शन किया

• साधना एक्सप्रेस, गाडरवारा

गाडरवारा । (राजेश नीरस) गणतंत्र दिवस के अवसर पर रुद्र मैदान पर आयोजित कार्यक्रमों में दक्ष इंटरनेशनल स्कूल, गाडरवारा द्वारा बोहनी के वीर सपूत शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा की जीवन यात्रा का भावनामई प्रदर्शन किया गया, छात्रों के शानदार प्रदर्शन पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दक्ष स्कूल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दक्ष ने व्यायाम-योग श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया। सांस्कृतिक, व्यायाम-योग और मार्च पास्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दक्ष इंटरनेशनल को श्रीमती कलावती ब्यारे , नगर

पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा और एस.डी.ओ.पी. ललित कुमार डागुर द्वारा सम्मानित कर सराहना की । ज्ञात हो की दक्ष इंटरनेशनल स्कूल, करेली के बच्चों ने ऑपरेशन सिंदूर का भव्य और भावनीय प्रदर्शन कर नगर पालिका करेली द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया जिसके लिए नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुशीला ममार और पूर्व राज्य सभा सांसद श्री कैलाश सोनी ने दक्ष को सम्मानित किया । इस गौरवपूर्ण उत्कृष्ट प्रदर्शन पर विद्यालय के संस्थापक जे.एस. यादव , चैतन्य यादव ने स्कूल प्रिंसिपल पी. के. चौधरी एवं प्रिंसिपल रोमी सिंह व विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं स्टाफ को बधाई दी ।

कल्याणपुर में व्याख्यान कार्यक्रम किया आयोजित

• साधना एक्सप्रेस, गाडरवारा

गाडरवारा*। (राजेश नीरस) गत दिवस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुर में रिटेल ब्रांच अंतर्गत व्याख्यान हेतु सेवानिवृत प्राचार्य उत्तमचंद विश्वकर्मा एवं शांतिकुंज हरिद्वार के विद्वान थम्मन सिंह शर्मा ने छात्र छात्राओं को कैरियर मार्गदर्शन एवं प्रतियोगी परीक्षा के बारे में बताया। उन्होने रिटेल व्यापार बढ़ाने के तरीके जैसे थोक व्यापार,फुटकर व्यापार, प्रोडक्ट, प्राइज, प्लेस, प्रमोशन के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की।

श्री शर्मा ने जीवन मूल्यों के बारे में छात्रों को मार्गदर्शन दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जीवन अमूल्य है इसे नशा,जैसी दुष्प्रवतियों से दूर रखे। इस अवसर पर जिले से

शाला में उपस्थित कैरियर काउंसलर प्रभारी इकबाल कुरैशी, मनीष शर्मा,ने छात्रों को उनके कैरियर सम्बन्धी मार्गदर्शन दिया। अंत मे आभार प्राचार्य ओमप्रकाश कौरव एवं धनसिंह कौरव ने किया।

कार्यक्रम के आयोजन मे शिवदास चढ़ार,दीपक शर्मा ,अवधेश कौरव,आरती विश्वकर्मा जीवनलता इक्का,मनीषा पटले,संजय पटेल सहित अन्य सहयोगी रहे।

सांदीपनि विद्यालय में 'तेजस्वी मेला' का भव्य आयोजन, विद्यार्थियों ने दिखाए उद्यमिता के हुनर

• साधना एक्सप्रेस, गाडरवारा

गाडरवारा I (राजेश नीरस) गत दिवस साईंखेडा के सांदीपनि विद्यालय में 'तेजस्वी कार्यक्रम' के अंतर्गत विद्यालय स्तरीय मेले का गरिमामय आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में उद्यमी सोच विकसित करना और उन्हें व्यावहारिक ज्ञान से रूबरू कराना था।

मेले में मुख्य आकर्षण कक्षा 11वीं के विद्यार्थी रहे जिन्होंने उद्यमिता (Entrepreneurship) के गुर सीखते हुए विभिन्न प्रकार के मॉडल्स तैयार किए। विद्यार्थियों ने न केवल अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया बल्कि विभिन्न स्टॉल लगाकर व्यापारिक कौशल का परिचय भी दिया। मेले के दौरान विशिष्ट अतिथियों ने प्रत्येक स्टॉल का बारीकी से निरीक्षण किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्रीमती ऋचा गुप्ता (स्थानीय व्यवसायी),अभिनव गर्ग (जिला तेजस्वी टीम प्रभारी), चंद्रकांत विश्वकर्मा (प्राचार्य, सांदीपनि विद्यालय) उपस्थित रहे। अतिथियों एवं विद्यालय के समस्त स्टाफ ने विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए मॉडल्स की सराहना की और वहां उपलब्ध उपयोगी वस्तुओं का क्रय कर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। स्कूल के प्राचार्य चंद्रकांत विश्वकर्मा ने बताया कि इस प्रकार के आयोजनों से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें भविष्य में स्वरोजगार व प्रबंधन की बारीकियों को समझने में मदद मिलती है। जिला प्रभारी अभिनव गर्ग ने विद्यार्थियों के नवाचारों की प्रशंसा करते हुए उन्हें 'तेजस्वी' अभियान के उद्देश्यों से अवगत कराया।

नाबालिग छात्रा को परेशान करने वाले आरक्षक पर एफआईआर

इन्दौर. लगातार किसी न किसी पुलिसकर्मी अथवा अधिकारी की अवैधानिक और सेवा विरूद्ध गतिविधि एवं आचरण के कारण दागदार हो रही इन्दौर पुलिस की छबि में कलंक का एक दाग और उस समय लग गया जब एक पुलिस कर्मी पर दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को परेशान करने से आक्रोशित हिन्दू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंच प्रदर्शन करते पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। मामला छत्रीपुरा थाने का है जहां डायल 100 पर तैनात आरक्षक दीपक के खिलाफ शिकायत की गई है। किशोरी को परेशान करने का आरोप लगाते हुए थाने पहुंचे लोगों का कहना है कि इससे संबंधित वीडियो भी सोशल साइट्स पर वायरल हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाते कहा है कि सिपाही दीपक कुछ दिनों से नाबालिग बालिका को परेशान कर रहा है। वह कॉलोनी में आकर खड़ा रहता है। कल जब वह कॉलोनी में पहुंचा तो लोगों ने घेर लिया और परेशान करने का आरोप लगाया तो वह इनकार करने लगा। लोगों ने वीडियो भी बनाया। जिसके बाद आरक्षक दीपक के खिलाफ दसवीं कक्षा की छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने कल देर रात एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र के छत्रीबाग में रहने वाली छात्रा ने अपनी दर्ज शिकायत में बताया कि कल वह कोचिंग जा रही थी। इसी दौरान जयरामपुर कॉलोनी के पास आरोपी आरक्षक दीपक ने उसका रास्ता रोका, हाथ पकड़ लिया और घर छोड़ने की बात कही। छात्रा ने किसी तरह अपना हाथ छुड़ाया और कोचिंग चली गई।पीड़िता ने शिकायत में यह भी बताया कि इससे पहले भी दीपक कई बार रास्ते में रोककर नाम-पता पूछ चुका था और लगातार उसका पीछा कर रहा था। आरोपी पुलिस की वर्दी में रहता था, जिस कारण डर के चलते उसने पहले किसी को यह बात नहीं बताई। लेकिन सिपाही दीपक के उसकी कालोनी और उसके घर तक पहुंचने के चलते उसने पूरी बात अपनी मां को बताई । जिसके बाद उन्होंने हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को जानकारी दी और उनके साथ थाने पहुंच एडिशनल डीसीपी हेमंत चौहान को पूरे मामले से अवगत कराया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी आरक्षक से पूछताछ कर छेड़छाड़ की धाराओं में एफआईआर दर्ज की। पुलिस के अनुसार सिपाही दीपक पर आरोप लगे हैं। आरोपों को लेकर लोगों से बात की जा रही है।

केवल लिखने से सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हो सकते, दस्तावेजी प्रमाण भी जरूरी है - हाईकोर्ट , जनहित याचिका निरस्त

इन्दौर. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की युगलपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई उपरांत उसे निरस्त करते टिप्पणी की कि यह याचिका जनहित में नहीं, बल्कि याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक हितों की रक्षा के लिए दायर की गई याचिका है। याचिकाकर्ता परमानंद सिसौदिया ने स्वयं को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हुए यह याचिका प्रस्तुत की और इसमें स्नेह नगर

में किए जा रहे निर्माण कार्यो में अवैध निर्माण हटाने, बिल्डरों के खिलाफ जांच कराने, उन्हें ब्लैकलिस्ट करने, निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने सहित कई राहत मांगी गई थी। सुनवाई दौरान पैरवी करते याचिकाकर्ता की ओर से एड्वोकेट स्वर्णशेखर सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता पूर्व में पार्षद रह चुके हैं और याचिका इसलिए दायर की है कि जो उनके परिजनों के साथ हुआ वो अन्य के साथ न हो। जिस पर शासन की ओर से पेश उपमहाधिवक्ता सुदीप भार्गव ने दलील दी कि याचिका से स्पष्ट है कि यह याचिका, याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों बहू और भतीजों के हितों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से दाखिल की गई है, जो प्रस्तावित निर्माण परियोजना से प्रभावित बताए जा रहे हैं उप महाधिवक्ता ने तर्क रखा कि याचिका याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों के हितों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से दाखिल की गई है। इसे जनहित याचिका नहीं माना जा सकता। उपमहाधिवक्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि याचिकाकर्ता ने स्वयं को सामाजिक कार्यकर्ता बताया है, लेकिन इसके समर्थन में कोई दस्तावेज नहीं पेश किए। इस पर कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने पूर्व में निर्णय दिया है कि केवल स्वयं को सामाजिक कार्यकर्ता बताना पर्याप्त नहीं है।

गलत कीटनाशक ने जलाई धनिया की फसल

गुना। जिले के बमोरी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम विशनवाड़ा और मानपुर के किसानों के लिए श्रीराम कृषि सेवा केंद्र की एक सलाह बर्बादी का सबब बन गई है। दुकानदार द्वारा धनिया की फसल के लिए अनुपयुक्त और तकनीकी रूप से प्रतिबंधित दवा बेचने के कारण दर्जनों किसानों की लहलहाती फसल जलकर राख हो गई है। मुआवजे और कार्रवाई की मांग को लेकर मंगलवार को पीड़ित किसान दूसरी बार जिला मुख्यालय पहुंचे और जनसुनवाई में कलेक्टर के समक्ष अपनी व्यथा सुनाई।

बिना योग्यता के बांट रहे जहर, धनिया के लिए बनी ही नहीं थी दवा मामले में चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि जिस ट्रेक्स नामक कीटनाशक को दुकानदार ने धनिया की फसल में डालने के लिए किसानों को दिया, वह असल में धनिया के लिए बनी ही नहीं है। दवा की बोतल पर कहीं भी धनिया की फसल का उल्लेख नहीं है। जानकारों का कहना है कि कृषि केंद्र चलाने के लिए कृषि विज्ञान या संबंधित विषय में डिग्री अनिवार्य है, ताकि सही परामर्श दिया जा सके, लेकिन यहाँ बिना किसी विशेषज्ञता के दुकानदार ने किसानों की लाखों की मेहनत पर पानी फेर दिया।।- सीताराम नाटानी

टैक्स चोरी और फर्जीवाड़े की बू: बिल में त्रस्ङ्ग गायब किसानों ने जनसुनवाई में जो पक्का बिल पेश किया है, वह भी संदेह के घेरे में है। बिल पर न तो बैच नंबर अंकित है और न ही SGST/CGST का हवाला दिया गया है।

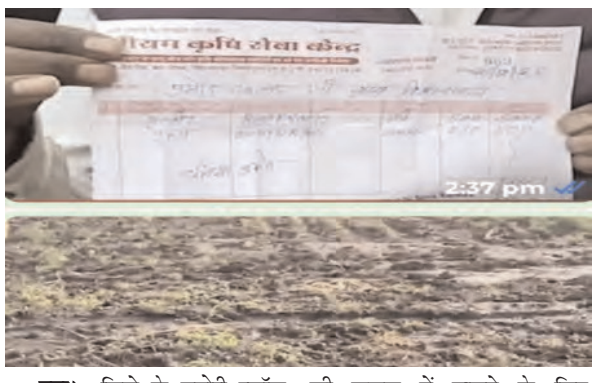

छात्रों को नागरिक कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों की दी जानकारी - पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प, अपना जिम्मेदारी समझने की दी सलाह

ब्यावरा. नगर में ग्रामोदय से अभ्युदय कार्यक्रम के तहत स्कूली और महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद और राघवम जन कल्याण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके नागरिक कर्तव्यों, सामाजिक जिम्मेदारियों और नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक प्रवीण पवार मुख्य

वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों का उल्लेख करते हुए युवाओं को उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन का स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया। पवार ने कहा कि विद्यार्थी देश का भविष्य हैं और यदि वे अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे, तो सच्चे नागरिक बनकर राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। उन्होंने कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों को समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला बताया। राघवम जन कल्याण संस्थान के अध्यक्ष मुकेश सेन ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी अच्छी आदतें बड़े बदलाव की नींव बनती हैं। सेन ने सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, परिवार प्रबोधन और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को अपनाने का आह्वान किया।

राज्यपाल श्री पटेल के मुख्य आतिथ्य में हुआ गणतंत्र दिवस समारोह का गरिमामयी समापन

भोपाल | राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल के मुख्य आतिथ्य में मध्यप्रदेश में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का गरिमामयी समापन गुरुवार को ऐतिहासिक 'बीटिंग द रिट्रीट' समारोह के साथ हुआ। जहांगीराबाद स्थित लाल परेड मैदान में इस भव्य समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश पुलिस ब्रास बैंड एवं आर्मी ब्रास बैंड द्वारा राष्ट्र भक्ति, अनुशासन और सांस्कृतिक

चेतना से ओत-प्रोत संगीतमय प्रस्तुतियों से संयम, एकरूपता और सैन्य परंपरा की गरिमा को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया।

उल्लेखनीय है कि 'बीटिंग द रिट्रीट' सैन्य एवं अर्ध सैनिक बलों की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली के साथ केवल भोपाल में ही इस ऐतिहासिक समारोह का आयोजन किया जाता है।

इस अवसर पर महापौर श्रीमती मालती राय, मुख्य सूचना आयुक्त श्री विजय यादव, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना, अपर मुख्य सचिव गृह श्री शिव शेखर शुक्ला, महानिरीक्षक पुलिस श्री इरशाद वली, कमांडेंट सातवीं वाहनी श्री हितेश चौधरी सहित आर्मी, पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

राज्यपाल श्री पटेल के आगमन पर पुलिस ब्रास बैंड द्वारा स्वागत धुन प्रस्तुत की गई। इसके पश्चात निरीक्षक श्री सुनील कटारे के नेतृत्व में आयोजित ब्रास बैंड कॉन्सर्ट में "वंदे-मातरम्" से आरंभ होकर, "मेरे देश की धरती", "पंख होते तो उड़ आती रे" की प्रस्तुति पुलिस बैंड द्वारा दी गई।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, मिनाक्षी पांडेय द्वारा डीके ऑफसेट प्रिंटर्स 50/6 शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र से मुद्रित एवं 111/44, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र से प्रकाशित ।
संपादक मिनाक्षी पांडेय एवं स्थानीय संपादक मनीष पांडेय मो.न- 7566293490 मेल sadhnaexpress@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल म.प्र रहेगा ।)| RNI NO. MPHIN/2022/84698